● वर्ष-3
● अंक-285
रायपुर, मंगलवार
09 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

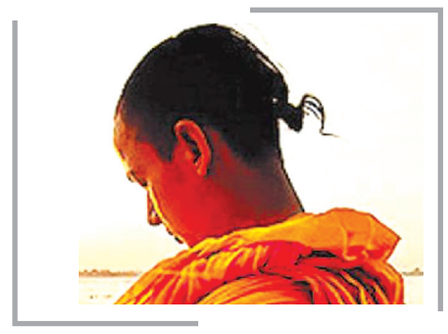

पेज-6›› हिंदू धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व

मुख्यमंत्री की पहलः लोगों को मिली एक और नई सुविधा

भूमि-मकान आदि के पंजीयन के समय ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा

राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में जुलाई माह से व्यवस्था लागू

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाईन शुल्क भुगतान की

सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाईव किया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री कराने हेतु ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।

गौरतलब है कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा हैं। ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाईन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिये जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाईन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाईन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभाग द्वारा ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।

मिशन गगनयान में लगेंगे स्वदेशी पैराशूट

250 डिग्री तापमान में भी करेंगे काम

नई दिल्ली। भारत के पहले ह्यूमन गगनयान मिशन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसरो इसके लिए अपने चार ट्रेंड पायलटों में से दो को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के लिए तैयार करेगी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल में रहने के तौर-तरीके सिखाएगी। वहीं गगनयान की सुरक्षित लैंडिंग

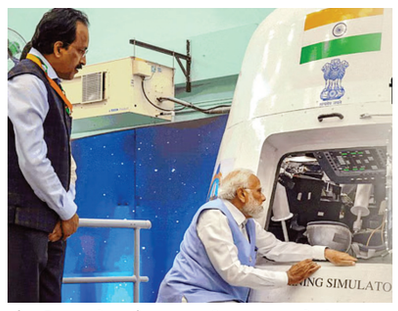

के लिए ड्रोग पैराशूट की जरूरत होगी। खास बात यह होगी कि ये पैराशूट्स पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। ये पैराशूट लगभग बन कर तैयार हैं।

हजरतपुर ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट्स फैक्टरी में बन रहे पैराशूट- सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाते हुए, भारत का पहला मानवयुक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन गगनयान मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए स्वदेशी ड्रोज पैराशूट का उपयोग करेगा। इन पैराशूट्स को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में हजरतपुर स्थित ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट्स फैक्टरी में बनाए जा रहा है। इन पैराशूट्स को इस्तेमाल रसार करम करने और तेजी से चलती वस्तुओं को स्थिर करने के लिए किया जाता है। इन ड्रोज पैराशूट्स का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाने के लिए किया जाएगा।

5,000 घंटे में बनती है एक पैराशूट कैनोपी - सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 28 पैराशूट सेट का ऑर्डर दिया है। इनमें से 12 इसरो को मिल चुके हैं और बाकी का काम अगले महीने पूरा हो जाएगा। 5.8 मीटर व्यास वाले ये कॉनिकल रिबन-प्रकार के पैराशूट, कैनोपी मेकेनिक्स को न्यूनतम करने और खुलने पर पैदा होने वाले झटकों को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे उतरने में आसानी हो। वहीं एक पैराशूट कैनोपी बनाने में कम से कम 5,000 घंटे की मेहनत लगती है। गगनयान मिशन के लिए चार प्रकार के पैराशूट का उपयोग किया जाएगा।

इनमें रिंग स्लॉट - एपेक्स कवर सेपरेशन (एसीएस) कैनोपी, ड्रोज पैराशूट - कॉनिकल रिबन कैनोपी, पायलट पैराशूट - रिंग स्लॉट कैनोपी, और मुख्य कैनोपी - सर्कुलर स्लॉटेड होते हैं।

नायलॉन से बने हैं पैराशूट

सूत्रों ने बताया कि 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलने वाले नायलॉन 66 जैसे विशेष कपड़े से बने हैं। डीआरडीओ और इसरो ने इन ड्रोज पैराशूट को डिजाइन और विकसित किया है। मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले पैराशूट के बारे में सूत्रों ने बताया कि यह 10 पैराशूटों का एक ग्रुप है। जब अंतरिक्ष यात्रियों वाला कैप्सूल पृथ्वी से 7 किलोमीटर की दूरी (ऊंचाई) पर पहुंचता है, तो वे काम करना शुरू कर देते हैं। दो एपेक्स कवर सेपरेशन (एसीएस) पैराशूट कैप को खींचकर दो ड्रोज पैराशूट को खोल देंगे, जिससे रफ्तार कम हो जाएगी, जो 190 मीटर प्रति सेकंड (11.4 किमी प्रति मिनट) तक पहुंच जाएगी। इसके बाद, तीन पायलट पैराशूट उतरने की रफ्तार को 10/12 मीटर प्रति सेकंड (600/720 मीटर प्रति मिनट) तक ले कर आएगा। पायलट पैराशूट मुख्य कैनोपी को खोलने के लिए बटन के रूप में कार्य करता है, जिनकी संख्या तीन होती है। प्रत्येक कैनोपी लगभग 1,000 किलोग्राम तक का भार झेल सकती है। इस प्रकार मुख्य पैराशूट प्रणाली में तीन कैनोपी कुल 3,000 किलोग्राम भार वहन कर सकती हैं।

दोबारा हो सकती है नीट-यूजी की परीक्षा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणियां

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पवित्रता खो गई है और यदि इसके प्रश्नपत्र के लीक होने की बात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्रश्नपत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है, तो यह जंगल में आग की तरह फैल जाएगा। पीठ ने कहा, एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है, इस पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

पीठ ने कहा, यदि परीक्षा की पवित्रता खो गई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। इसके साथ ही यह भी कहा कि यदि लीक की बात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई थी, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।

पीठ ने कहा, जो हुआ, हमें उसके बारे में आत्म-निषेध नहीं करना चाहिए। यह मानते हुए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है, वह उनकी पहचान के लिए क्या करेगी जिन्हें लीक प्रश्नपत्र मिला?

शीर्ष अदालत विवादों से घिरे नीट-यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 5 मई की परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं, तथा इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

पीठ ने पूछा, कितने गलत काम करने वालों के परिणाम रोके गए हैं, और हम ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक वितरण जानना चाहते हैं।

केंद्र और एनटीए, जो नीट यूजी आयोजित करता है, ने हाल ही में अपने हलफनामों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि परीक्षा को रद्द करना प्रतिकूल होगा। केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं।

इन उम्मीदवारों को या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। एनटीए ने 23 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची की घोषणा की।

रूपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राजद उम्मीदवार को पप्पू यादव का समर्थन

पटना। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रूपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार बीमा भारती को 'पूर्ण समर्थन'देने की सोमवार को घोषणा की। यादव ने हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में भारती को हराया था। यादव ने 'एक्स' पर कहा, विचारधारा बड़ी चीज है, राजनीति में आज यह विलुप्त हो रही है। लेकिन मैं विचारधारा की राजनीति का वाहक हूं, मैं कांग्रेस विचारधारा के साथ हूं। इसलिए मेरे प्रति तमाम निजी नफरत को खारिज करते हुए रूपौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को मेरा पूर्ण समर्थन है। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी 'जन अधिकार पार्टी' का कांग्रेस में विलय कर पार्टी टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी लेकिन राजद द्वारा बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारने के बाद यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना करने के बाद भारती फिर से राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं।

प्रमुख समाचार

सेना के गश्ती दल पर आतंकियों का हमला, पांच जवान बलिदान

बिलावर। कठुआ के बिलावर उपजिले में बदनोता के बरनूड इलाके में जेंडा नाले के पास सेना के एक वाहन पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। आतंकी हमले में पांच जवान बलिदान हो गए वहीं कुछ अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। घायल जवानों को पीएचसी बदनोता में प्राथमिक उपचार के बाद उपजिला अस्पताल बिलावर में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना का यह वाहन इलाके में गश्त पर था जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। आतंकियों की ओर से ग्रेनेड फैंका गया जिसके बाद गोलाबारी शुरू कर दी गई। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। अंतिम समाचार मिलने तक दोनों ओर से गोलाबारी का सिलसिला जारी था। हालांकि जवानों के बलिदान होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर साढ़े तीन बजे के लगभग आतंकियों ने 22 गढवाल राइफल्स के जवानों को निशाना बनाते हुए जेंडा नाले के पास ग्रेनेड फैंका। बताया जा रहा है कि आतंकी ऊंचाई वाले इलाके में थे।

न्यायालय ने जयराम रमेश को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

प्रयागराज। जिला न्यायालय ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्र ने वाद दायर किया था। जिसके आधार पर कोर्ट ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। अब नोटिस जारी कर कांग्रेस नेता से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। बता दें कि जयराम रमेश ने एक जून को एक बयान जारी कर कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन पर धमकी दे रहे हैं। परिणाम भाजपा के पक्ष में लाने के लिए वह 150 से अधिक कलेक्टर्स को फोन कर चुके हैं। उनका यह बयान उनके आधिकारिक ट्विटर अब (एक्श) पर भी पोस्ट किया गया था। जयराम रमेश ने अमित शाह के इस कृत्य को शर्मनाक बताया था। इस बयान के खिलाफ भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुशील कुमार मिश्र ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है।

प्रशांत किशोर के पास गए तो लालू की पार्टी कार्रवाई करेगी?

पटना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जारी किए गए पत्र का राज से पर्दा नहीं पा रहा। अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने जगदानंद सिंह ने आपलोग मामले को घुमाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। स्पष्ट कहा कि अगर इस मामले में ज्यादा सवाल पूछेंगे तो मैं उठकर चला जाउंगा। दरअसल, राजद की ओर से जनसुराज और प्रशांत किशोर को लेकर एक पत्र जारी किया गया था। इसमें राजद का नाम लिखा हुआ था और इसपर जगदानंद सिंह के हस्ताक्षर थे। पत्र में राजद कार्यकर्ताओं, नेताओं से अपील की गयी है कि वह राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की प्रस्तावित पार्टी जन सुराज में शामिल नहीं हो। इस पत्र में जन सुराज को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तक कह दिया गया था। उसके बाद से बिहार की सियासत गरमा गई। बता दें कि सोमवार को राजद कार्यालय में लंबे अरसे के बाद जगदानंद सिंह ने बाढ़ के मुद्दों पर बातें की। उन्होंने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। बाढ़ पर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जिम्मेदार पद पर हैं। उन्हें इस मामले को देखना चाहिए।

अब रहीमनगर, मकानों पर लगे लाल निशान

लखनऊ। अकबरनगर को जमींदोज करने के बाद कुकरैल रिवर फ्रंट के रास्ते में आ रहे रहीमनगर, खुर्रमनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंतनगर, अबरारनगर के अवैध निर्माण गिराने के लिए प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार से सर्वे शुरू कर दिया। पहले दिन 20 मकानों में लाल निशान लगाया गया। यह देख इनमें रहने वाले परिवार बिलख उठे। सुबह 11:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मुकेश वैश्य के संयुक्त नेतृत्व में सिंचाई विभाग की टीम ने रहीमनगर बंधे के पास कुकरैल से 50 मीटर के दायरे की नापजोख शुरू की। टीम ने लगभग एक किमी तक सर्वे किया और कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाली जमीन पर लाल निशान लगाया। टीम जैसे ही रहीमनगर में दाखिल हुई, घरों से पुरुष, महिलाएं व बच्चे निकल आए। मकानों पर लाल निशान लगना शुरू हुए तो महिलाएं रोने लगीं। बिलखते हुए टीम से कहा, जब मकान बन रहे थे तो कोई रोकने क्यों नहीं आया?

उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधू-शरत कमल होंगे भारत के ध्वजवाहक

नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में अब 18 दिन शेष हैं। भारतीय दल इसके लिए पूरी तैयार है। भारत को इस बार पेरिस जाने वाले खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू और दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी ए शरत कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे। वहीं, ओलंपिक पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा और इसके लिए भारत 100 से अधिक खिलाड़ियों का दल भेजेगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी, जिसने दो ओलंपिक पदक जीते हैं, पीवी सिंधू, टेबल टेनिस के दिग्गज ए. शरत कमल के साथ उद्घाटन समारोह में महिला ध्वजवाहक होंगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एथलीट पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

नए कानून बनाना सही दिशा लेकिन अनसुलझे मुद्दों पर भी बात हो

प्रकाश सिंह

औपनिवेशिक दौर के प्रमुख आपराधिक कानूनों-भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम-की जगह लागू तीन नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में मामले दर्ज होना शुरू भी हो गए हैं। नए कानूनों में एफआईआर, जांच एवं सुनवाई के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय कर दी गई है। अब लोग बिना थाना गए ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। देश के किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज हो सकेगी। नए बीएनएस में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे-विवाह का वादा करके धोखा देने पर 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति-समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग मामले में आजीवन जेल तथा छीन-झपट के लिए तीन साल की जेल। यूएपीए जैसे आतंकवाद-रोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है।

औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और कानूनों को वर्तमान समय के अनुरूप बनाने का यह ऐतिहासिक कदम प्रशंसनीय है, पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जो अब भी अनसुलझे हैं। औपनिवेशिक काल के कानूनों में 1162 धाराएं थीं, जबकि नए कानूनों में 1059 धाराएं हैं। जाहिर है, अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 2,221 धाराओं से जूझना होगा। बीएनएस जैसे मूल कानून को पहले दर्ज किए गए मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए नए कानून के लागू होने से पहले के अपराधों को आईपीसी (भादंसं) के तहत निपटाया जाएगा, जबकि नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद किए गए अपराधों को बीएनएस के तहत निपटाया जाएगा। हालांकि बीएनएसएस एवं बीएसए जैसे प्रक्रियागत कानूनों को पहले दर्ज किए गए मामलों पर लागू किया जा सकता है। ऐसे में न्यायालय में उन सभी मामलों में विवाद होने की आशंका है, जो नए कानून के लागू होने से पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन उनमें नए प्रक्रियात्मक कानून को लागू किया जाएगा।

तीनों प्रमुख कानूनों में अलग-अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग समय पर संशोधन किए गए हैं। मसलन, सीआरपीसी की धारा 357 (मुआवजा देने के आदेश से संबंधित) में आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा संशोधन किए गए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसे कई संशोधन किए गए। ये संशोधन राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित और लागू किए गए, क्योंकि राज्य की विशेष जरूरतों के लिए ऐसा करना जरूरी पाया गया। नए लागू किए गए कानूनों में राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों को शामिल नहीं किया गया है। कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने जब इन नए कानूनों का

विरोध किया, तो केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकारें सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने को स्वतंत्र हैं।

नए कानून में गैर-कानूनी कृत्य और आतंकवादी कृत्य की परिभाषा एवं दंड को बीएनएस के दायरे में लाया गया है। तीन वर्ष से सात वर्ष के बीच कारावास की सजा वाले मामलों में प्रारंभिक जांच का प्रावधान समस्याओं का पिटारा खोल देगा, जहां पुलिस जांच करने से इन्कार कर सकती है, जिससे जनता में असंतोष पैदा होगा। बीएनएसएस की धारा 173(3) में कई अस्पष्टताएं हैं। इस बात की आशंका है कि इससे व्यापक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, कानूनी बिरादरी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत की सुनवाई होगी, तो बचाव पक्ष के वकील, जो अदालत में गवाहों से पूछताछ करेंगे, वे उस आरोपी के सीधे संपर्क में नहीं रह पाएंगे, जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीएनएसएस कानून के तहत कई प्रगतिशील प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल तकनीक अनिवार्य है, जैसे तलाशी की वीडियोग्राफी और ई-कोर्ट कार्यवाही। जबकि अभी थानों, जांच अधिकारियों, अदालतों और जेलों में अब भी आवश्यक बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, प्रणालियों और प्रोटोकॉल का विकास, विशेष तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण जरूरी हैं। ऐसे में ई-कोर्ट कार्यवाही और इलेक्ट्रॉनिक समन जैसे बीएनएसएस के प्रावधानों को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी।

इसके अलावा, कई राज्यों में पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इससे उन्हें नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा आएगी और प्रक्रियागत देरी तथा कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। ऐसी खबरें भी आई हैं कि नए मामले दर्ज करने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम तथा आईसीजेएस के साथ इसके इंटरफेस को भी नए कानूनों के अनुरूप अपडेट नहीं किया गया है, जिससे परिचालन एवं तकनीकी संबंधी गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जांच के लिए फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य करना स्वागतयोग्य है और विभिन्न जांच प्रक्रियाओं में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार को मंजूरी देना एक सकारात्मक कदम है। लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में इन प्रक्रियाओं को अगर गलत तरीके से निष्पादित किया गया, तो अपराधी दोषमुक्त हो सकते हैं।

वनकर्मियों के आवासों का हाल बेहाल

वर्षों से नहीं हुई मरम्मत और न ही रंगाई पोताई, हर साल आता है बजट

बीजापुर। बीजापुर में जिला मुख्यालय में वनविभाग के कर्मचारी जिन शासकीय भवनों में रहते हैं उनकी हालत बेहद ख़राब व जर्जर है। किसी के आवास का दरवाजा टूटा है तो किसी की खिड़की। वहीं कई वर्षों से आवासों में रंगाई पोताई तक नहीं कराई गई है। ऐसे में वनविभाग के इन आवासों की मरम्मत न होने से इनमें परिवार के साथ साथ वनकर्मियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवासों में रहने वाले लोगों ने बताया की कई बार हम अपने आवासो की मरम्मत के लिए लिखके दे चुके है। वहीं बीच-बीच में विभाग के लोग भी समस्या जानने के लिए आते हैं और समस्याएं लिखकर ले जाते हैं लेकिन कई साल हो गए विभाग की ओर से हमारे आवासो में किसी भी प्रकार का मरम्मत और न ही रंगाई पोताई का काम किया गया है। जिससे आवासों की हालत सही नहीं है।

जिला अस्पताल के सामने बने वनविभाग के कर्मचारियों के 8 आवास है। इन आवासो में सबसे बड़ी समस्या शौच की है। यहाँ पर रह रहे लोगों ने बताया की यहाँ पर जितने भी क्वाटर है उनमें अधिकतर का लेटबाथ चोक है। पानी की निकासी भी सही नहीं है। जिससे शौच के लिए बड़ी समस्या होती है। यहाँ पर कई कर्मचारी है जो इन समस्याओं के कारण दूसरे जगह पर या किराये पर रहने को मजबूर है।

वहीं इन सरकारी आवासो में 10 साल पहले विभाग ने खानापूर्ति के लिए सीट लगा कर अपना पल्ला झाड लिया था उसके बाद वनविभाग ने वनकर्मियों के इन आवासो की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वहीं पिछले 3 से 4 साल हो गए कर्मचारियों के इन आवासो में किसी तरह का कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। कर्मचारी अब अपने पैसों से अपने आवासो की मरम्मत करवा रहे है। वहीं कर्मचारियों के वेतन से हाउस रेंट की भी कटौती विभाग करता है लेकिन विभाग अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है यह समझ से परे है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हर साल कर्मचारियों के आवासो की मरम्मत के लिए बजट आता है। लेकिन इस बजट का इस्तेमाल वनविभाग के जिम्मेदार अफसर कहाँ करते है ये जाँच का विषय है। डीएफओ रामाकृष्णा रंगानाघा वाय ने इस संबध में कम बजट का हवाला देते हुए कहा की हर साल 4 से 5 लाख रूपये का बजट आता है। लेकिन जिले में कुल 140 से 150 शासकीय आवास है। ऐसे में इतने कम बजट में सभी आवासो का मरम्मत करवाना आसान नहीं है । जहाँ पर प्राथमिकता होती है वैसे आवासो में मरम्मत का कार्य कराया जाता है और जो कर्मचारी सालों से इन आवासो में रह रहे है उन्हें भी छोटे छोटे कामों को करवाना चाहिए ये उनकी भी जिम्मेदारी है।

50 से अधिक लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत

बिलासपुर। जिले के रतनपुर में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। खराब पानी की वजह से 50 से ज्यादा लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई। जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिसमें रतनपुर अस्पताल में 15 मरीज और 3 गंभीर मरीजों को सिम्स में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रविवार को रतनपुर का दौरा किया है।

रतनपुर के महामायापारा में रहने वाले 50 लोगों डायरिया की चपेट में आ चुके है। बिगड़ते हालत को देखते हुए सीएमएचओ डॉ प्रभात श्रीवास्तव और डीएचओ डॉ। विनोद तिवारी ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र का सर्वे किया और घर-घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। स्वास्थ्य विभाग ने घरों में क्लोरिन की दवा का वितरण किया। साथ ही मरीजों को एंटी डायरियल और अन्य दवा देकर आराम करने की सलाह दी है।

जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम को सर्वे के दौरान घरों में लगे नल के कनेक्शन आसपास के नालियों से होकर गुजरते मिले हैं। जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। सर्वे में करीब 250 घरों तक टीम पहुंच चुकी है। प्रभावित इलाके के आसपास के क्षेत्र में बोर का भी सर्वे किया जाएगा, ताकि उससे पानी पीने वालों की जांच की जा सके।

मनेंद्रगढ़ में वनविभाग के कामों में भ्रष्टाचार का आरोप कार्रवाई के बजाए मरम्मत का राग अलाप रहे अफसर

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र के कुदरा बीट में वन्यप्राणियों के लिए तालाब का निर्माण कराया गया था।लेकिन ये तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गुणवत्ताहीन काम के कारण इस तालाब में जानवरों के लिए तो छोड़िए कीड़े मकोड़ों के लिए भी पानी नहीं रुकता।इस तालाब को बनाने के लिए कितना भ्रष्टाचार किया गया होगा,इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता कि तालाब का निर्माण किस मद से किया गया है इसकी जानकारी भी आपको नहीं मिलेगी।

वन विभाग में निर्माण कार्य का पूरा लेखा जोखा अधिकारियों को ही देखना होता है। चाहे डब्लूबीएम सडक निर्माण, रपटा, पुल पुलिया, स्टाप डेम या कोई भी निर्माण कार्य हो वनविभाग के अधिकारी ही इन कार्यों का ठेकेदार से लेकर इंजीनियर तक सर्वे सर्वा होते हैं। इसलिए इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं होता है। क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों को यह बात अच्छे से पता है कि हमारे किए गए कार्यों का सत्यापन हम ही कर सकते हैं।

वनों के आसपास बसे ग्रामीणों का आरोप है कि वनविभाग जो भी काम करवाता है उसमें गुणवत्ता नहीं होती।ताजा उदाहरण स्टाप डैम का है जो हल्की बारिश में ही फूट गया।यदि गुणवत्ता होती तो गर्मियों में डैम में पानी होता जिसका इस्तेमाल मवेशी करते।वहीं ग्रामीण गणेश तिवारी का कहना है कि वन्यजीवों के लिए रेंजर के द्वारा जलाशय का निर्माण करवाया गया। जो पहली बरसात में बह गया।

इस संबंध में जब हमने वन विभाग के उप मंडल अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि जिस कदर से बताया जा रहा है कि जिस तालाब का निर्माण कराया गया था वह अभी पहली बारिश में ही पूरी तरह से बह गया है। अगर ऐसा कुछ है तो उस सुधारा जाएगा। दोबारा से निर्माण कर दिया जाएगा।

अफसर का कहना है कि यदि तालाब टूटा है तो उसकी दोबारा मरम्मत कर दी जाएगी।लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा गया कि जिसने निर्माण कार्य में लापरवाही बरती है उस पर क्या कार्रवाई होगी।कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल में अफसर भी शामिल हो।इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही।

वनविभाग के अंदर होने वाले कार्यों की यदि बात की जाए तो किसी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर उस काम को दोबारा कराने या फिर मरम्मत का प्रवाधन होता है।यही प्रावधान अफसरों से लेकर ठेकेदारों को बचाते आ रहा है। मनेंद्रगढ़ वनमंडल के वन परिक्षेत्र कुंवारपुर में इसी तरह के कामों की भरमार देखने को मिल सकती है।

कांग्रेस पार्षद के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर

- 24 दुकानें जमींदोज, पूर्व मंत्री का धौंस दिखाकर किया था कब्जा

दुर्ग। जिले में अवैध अतिक्रमण को लेकर अब जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पर है। जिला प्रशासन ने धमधा ब्लॉक के ग्राम जोगी गुफा में कांग्रेस पार्षद की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 24 दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। इस कार्रवाई में तहसीलदार, पटवारी, जिला पंचायत, जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय थाना पुलिस बल की सुरक्षा में अवैध कब्जे को ढहाने की कार्रवाई की गई।

दुर्ग के ग्राम जोगी गुफा में सोमवार सुबह ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचे और ग्राम के सरपंच संतोष बंजारे द्वारा खसरा नम्बर 06 पर किये गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। तहसीलदार के अनुसार जल संसाधन विभाग की भूमि खसरा नंबर 6, पश्चिम में 2941 वर्ग फीट और दक्षिण में 2601 वर्ग फीट पर सरपंच संतोष बंजारे ने जल संसाधन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से 24 दुकानों का निर्माण कर लिया था। सरपंच पर आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में सरपंच बंजारे ने साजा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे का धौंस दिखाते हुए अवैध रूप से

इन दुकानों का निर्माण कराया था। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी अवैध दुकानों का मुद्दा बीते दिनों जिला पंचायत सामान्य सभा में उठा था।

साजा विधायक ईश्वर साहू ने बैठक के दौरान इस पर सभी अधिकारियों से जवाब मांगा था। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जांच में पाया कि उक्त भूमि जल संसाधन विभाग के अधीन है। जिसके बाद जमीन पर बनी दुकानों पर कार्रवाई के लिए न्यायाल से अनुमति लेकर आज कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद सरपंच ने जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र साहू पर आरोप लगाया है कि जितेंद्र साहू ने इन दुकानों में 3 दुकानों की मांग की थी। उनके द्वारा इसका विरोध करने पर राजनीतिक दबाव बनाते हुए यह कार्रवाई की गई है। सरपंच ने दुकानों के आबंटन के लिए आवेदन मंगाकर डेढ़ लाख रुपये की राशि भी जमा करा ली थी।

खेत की जुताई के दौरान मिलीं सालों पुरानी खंडित मूर्ति

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में पेण्ड्रा के धनपुर गांव में किसान की जमीन पर खेत निर्माण और जोताई के दौरान सैकड़ों साल पुरानी खंडित मूर्ति और मंदिर के अवशेष मिले हैं। मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दे दी गई है वहीं ग्रामीणों की मानें तो इस इलाके में हमेशा खुदाई के दौरान मूर्ति और मंदिर के अवशेष मिलते है और इन्हें सहेजने की जरुरत है।

पौराणिक नगरी के नाम से जिले में अपनी अलग पहचान रखने वाली धनपुर गांव के सुरंगटोला में रहने वाले किसान छोटे लाल मराबी के खेत में कल शाम जेसीबी लगाकर खेत निर्माण कार्य चल रहा था तभी खुदाई के दौरान खेतो से मूर्तियों व मंदिर के अवशेष मिले हैं।

देखने में यह मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी प्रतीत होती हैं मूर्तियों एवं मंदिरों के अवशेष जमीन से निकलने की जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की मूर्तियों और मंदिर के अवशेष इन इलाकों में लगातार खुदाई या फिर अन्य कहीं अलग-अलग जगह पर अवशेष मिलते रहते हैं। यह अवशेष सैकड़ो साल पुराने हो सकते है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि जब भी कभी खुदाई के दौरान ज़मीनों से मूर्तियां निकलती है तो उसे प्रशासन के द्वारा ले जाया जाता है लेकिन उन मूर्तियों के अवशेष को सहजने एवं संवारने की आवश्यकता है पर प्रशासन की कोताही सामने दिखाई देती है। क्योकि इन्हें व्यवस्थित नहीं रखा जाता।

साथ ही समय के साथ जरूरत है कि इन्हें सहज के रखा जाए। ताकि यह प्राचीन कालीन मूर्तियां पर्यटकों के देखने समझने के लिए सुरक्षित मिल सके। गांव के साथ ही आसपास के गांव के लोग इन निकली मूर्ति के अवशेषों को देखने के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं।

अदाणी पॉवर लिमिटेड ने प्रभावित 22 लोगों को स्वरोजगार के लिये राशि प्रदान की

रायगढ़। अदाणी पावर लिमिटेड,रायगढ़ द्वारा पुसौर ब्लॉक में जमीन प्रभावितों को स्व रोजगार के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की गई। ग्राम छोटे भंडार में स्थित संयंत्र परिसर में शुक्रवार, 5 जुलाई को आयोजित शिविर में उपस्थित हुए 22 भूमि प्रभावित खाताधारकों को आपसी समझौते के तहत उनके स्वरोजगार के लिए और नौकरी के बदले 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि का चेक प्रदान कि गया। प्राप्तकर्ताओं में ग्राम कलमा के 16, छोटे भंडार, बड़े भंडार और सरवानी के कुल 6 खाताधारक शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को मुआवजा देना था जिनकी जमीन संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई।

अदाणी पावर लिमिटेड ने रोजगार के बजाय एकमुश्त राशि का विकल्प चुनने वाले पात्र खाताधारकों को एक समझौते के तहत एक मुश्त राशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। जिसके लिए आसपास के पांच गांवों के कुल 174 खाताधारकों ने एक आवेदन देकर एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने की इच्छा जताई थी। इस तरह अदाणी

पावर लिमिटेड,रायगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में आज तलक कुल 8.70 करोड़ रुपए पात्र खाताधारकों को चेक के माध्यम से वितरित किये गए। अदाणी पावर लिमिटेड ने रोजगार के बजाय एकमुश्त राशि का विकल्प चुनने वाले पात्र खाताधारकों को एक समझौते के तहत एक मुश्त राशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। जिसके लिए आसपास के पांच गांवों के कुल 174 खाताधारकों ने एक आवेदन देकर एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने की इच्छा जताई थी। इस तरह अदाणी पावर लिमिटेड,रायगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में आज तलक कुल 8.70 करोड़ रुपए पात्र खाताधारकों को चेक के माध्यम से वितरित किये गए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, मचा हड़कप

कोरबा। कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत इमली छापर स्थित मुस्कान पेट्रोल पंप में रात लगभग दो बजे वक्त हड़कंप मच गया। जब पंप परिसर में खड़ी चार वाहनों में भीषण आग लग गई। पहले तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर उस चारपहिया वाहन में लगी आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप में रखें अग्नि शामक यंत्र, रेत और पानी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग तेज हवाओं के साथ फैलने लगी और एक-एक कर चार वाहन चपेट में स्कूटी, मालवाहक ऑटो और क्रेन तक जा पहुंची। घटना की सूचना पर कुसमुंडा थाना प्रभारी रूपक शर्मा, एस आई राकेश गुप्ता, आरक्षक लेखराम धीरहे मौके पर पहुंचे और मौके पर जाम भीड़ को आग से दूर रहने की हिदायत दी।साथ ही देते घटनास्थल से नजदीक एसईसीएल कुसमुंडा की दमकल विभाग के साथ कोरबा से दमकल विभाग के वाहन को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने निर्देश दिया गया। पेट्रोल पंप से उठी आग की चिंगारी ने एक-एक कर चार वाहन को स्वाहा कर दिया। लगभग एक घंटे बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची।

बिलासपुर खनिज विभाग का एक्शन, टीम ने मारा छापा

बिलासपुर। बिलासपुर खनिकर्म विभाग ने बीती रात में ग्राम कुकुर्दीकला, अमलडीहा, उदयबंद, गतौरा लोधीपारा, लोफंदी, सेंदरी, कछार निरतू और धुरीपारा मंगला क्षेत्र में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की। रात लगभग 3 बजे ग्राम कुकुर्दीकला, थाना एवं तहसील-पचपेड़ी में शिवनाथ नदी के भीतर दो नग चैन माउंटेड मशीन को खनिज रेत के अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर नदी के बाहर खड़ा कर जब्त कर सील कर दिया गया है। दो नग लोड हाइवा को नदी के रास्ते में फंसे होने के कारण चैन माउंटेड मशीन मालिक के सुपुर्दगी में दिया गया। एक हाइवा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जब्त कर पुलिस थाना पचपेड़ी की अभिरक्षा में रखा गया है। ग्राम गतौरा में मुरूम मिक्स चिल्ही पत्थर का अवैध परिवहन करते दो ट्रेक्टर को जब्तकर पुलिस थाना सरकंडा के अभिरक्षा में रखा गया है। ग्राम कछार मे खनिज रेत के अवैध परिवहन करते एक ट्रेक्टर को जब्त कर पुलिस थाना कोनी के अभिरक्षा में रखा गया है। सभी के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला गिरफ्त में

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले में आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले फरार मुख्य आरोपी रितेश कुमार सुल्तानिया को साइबर सेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में एक अन्य आरोपी जिसने सट्टा एप बनाया वो अब तक फरार है। उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आईपीएल में ऑन लाइन सट्टा खिलाने का कारोबार फैलाने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी रितेश सुल्तानिया, पिता राम अवतार सुल्तानियास उम्र 30 साल, निवासी बजरंग चौक पेण्ड्रा को साइबर सेल की टीम ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जबकि एक अन्य मुख्य आरोपी मधुर जैन की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। शॉटकट में कम समय में पैसा कमाने के लिए मधुर जैन ने राजा रानी एप बनाया था और उस एप के जरिये आरोपी ऑन लाइन सट्टे का कारोबार जिले में संचालित कर रहा था। पुलिस ने मामले में पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

यूट्यूबर रवि दीवान की सड़क हादसे में मौत

महासमुंद। ग्राम केरामुड़ा निवासी यूट्यूबर

रवि दीवान का बीती रात सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र शोक की लहर दौड़ पड़ी। रवि दीवान विभिन्न छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करने के साथ ही अपने यूट्यूब चैनल में विभिन्न मनोरंजक व प्रेरणास्पद लघु फिल्म बनाकर लोगों को एक संदेश भी दिया करते थे। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात श्री दीवान अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद अपने मित्र के घर ग्राम खोपली दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां से कार्यक्रम पश्चात रात्रि में गृहग्राम केरामुड़ा लौट रहे थे कि रास्ते में पचरी व कुल्हरिया के बीच टर्निंग में बाइक अनियंत्रित हो गई जिससे वह सडक किनारे जा गिरा और गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना राहगीरों ने डायल 112 को दी और पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामनुजगंज में रविवार को जल जीवन मिशन योजना के कार्य के लिए स्ट्रक्चर ट्रैक्टर में लोड कर ट्रैक्टर राष्ट्रीय राज्य मार्ग 343 से होकर ग्राम मितगई जा रहा था इसी दौरान नगर सेना के आगे तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक युवक मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। घटना के बाद मार्ग अवरुद्ध की स्थिति निर्मित हो गई हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा ट्रैक्टर मार्ग से हटवाया जिससे आगमन सामान्य हो सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर में बलरामपुर से जल जीवन मिशन योजना के लिए स्ट्रक्चर लोड करके ड्राइवर सहित पांच लोग ग्राम मितगई जा रहे थे इसी दौरान शाम 6:30 बजे के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक की मौत हो गई वहीं तीन लोग घायल हो गए। मृतक का नाम वासीद पिता घूरे खान उम्र 30 वर्ष ग्राम मलीयाना, थाना ट्रांसपोर्टनगर जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है।

बस्तर में गोंचा पर्व के दिन उत्पात, युवक को लोहे की सरिया से पीटा, बाइक भी जलाई

जगदलपुर। बस्तर में गोंचा पर्व के दिन असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। जगदलपुर शहर के सब्जी बाजार संजय मार्केट में तीन बदमाशों ने एक युवक की रॉड और डंडे से पिटाई कर दी। किसी शख्स ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर उसे वायरल कर दिया। तीन बदमाशों में से एक बदमाश को जिला प्रशासन ने जिला बदर किया है। लेकिन यह बदमाश शहर के सबसे व्यवस्तम इलाके में खुलेआम घूमते और मारपीट करते हुए नजर आया।

दूसरी घटना शाम करीब 5 बजे की है। बोरपदर गांव का निवासी करन अपने एक साथी के साथ शहर में किताबें खरीदने पहुंचा था। किताबें खरीदकर युवक वापस अपने घर जा रहा था तो पुराने पुलिया के पास कुछ युवकों ने करन और उसके साथी पर तुपकी चला दी। फिर विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने मिलकर करन और उसके साथी की पिटाई कर दी। करन के सिर में चोट लगी है। करन ने कोतवाली थाने में आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

तीसरी घटना देर शाम की है। पुरानी मंडी के पास दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों बाइक सवार आपस में भीड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक ने दूसरे युवक की बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बाइक सवारों के दूसरे साथी भी वहां पहुंच गए। फिर जमकर हंगामा बरपा। इस घटना का भी वीडियो शहर में वायरल होने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई। दोनों गुट के युवक कोतवाली थाना परिसर पहुंचे, लेकिन वहां भी विवाद करते रहे।

लोगों का कहना है कि कि असामाजिक तत्वों में पुलिस का डर नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। 2 मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपियों के तलाश में जुट गई है। जगदलपुर सीएसपी उदित पुष्कर ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही है।

तीरथगढ़ वॉटरफॉल पर सुरक्षा की गारंटी नहीं

- छत्तीसगढ़ में ये कैसा एन्जॉय, पैसा भी ज्यादा, जोखिम में पर्यटकों की जान

जगदलपुर। बरसात के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही बस्तर जिले के वॉटरफॉल में लोकल निवासियों के साथ ही बाहर से भी रोजाना सैकड़ों पर्यटक बस्तर के इस खूबसूरती को निहारने के लिए आ रहे है। लेकिन इस पर्यटन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां पर्यटकों अपनी जान को जोखिम में डालकर एन्जॉय तो कर रहे है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नही है। यहां पर रायपुर से लेकर विशाखापत्तनम, ओड़िसा के अलावा अन्य जगहों से पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं। लेकिन तीरथगढ़ वॉटरफॉल पर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा है।

बताया जा रहा है कि जगदलपुर शहर में चित्रकोट, मिनी गोवा, तामड़ागुमर, तोपर, बिजाकासा, गुलमी, चित्रधारा के अलावा और भी कई जगह है। जहां लोग एन्जॉय करने के लिए जाते हैं। जहां कई बार बड़ी घटनाएं घट चुकी है।

तीरथगढ़ वॉटरफॉल- यह जगह देखने में जितनी सुंदर है। उतना ही यहां पर दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। जिसकी बात करें तो यहां कुछ साल पहले टॉप पर बैठे पति-पत्नी में पत्नी की फिसलकर गिर जाने से मौत हो गई थी। इसके अलावा इस जगह से नीचे एक छोटा सा झरना भी है। जिसके नीचे कुंड बना हुआ है। जहां कई हादसे हो चुके हैं और कईयों की डूबने से मौत हुई है।

चित्रकोट वॉटरफॉल- इस वॉटरफॉल को मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर भी कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं। अधिकतर देखा जाए तो कइयों ने इस

वॉटरफॉल से छलांग लगाकर अपनी जान दे चुके हैं। इसके अलावा इस फॉल से डॉक्टर पति-पत्नी गिर गए थे। लेकिन बाद में मछुआरों की टीम ने बचा लिया था।

गुलामी वॉटरफॉल- ये वॉटरफॉल छत्तीसगढ़ और ओड़िसा सीमा के बीच है। यहां भी काफी संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन इस वॉटरफॉल में भी कई युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है। इसके अलावा कुछ वर्ष पहले घूमने आए जोड़ों से कुछ लोगों ने पैसे की मांग भी की थी। लेकिन नहीं मिलने पर हत्या तक हो चुकी है।

मिनी गोवा- बस्तर के युवाओं ने कुछ वर्ष पहले इसकी खोज की थी। लेकिन यह जगह इंस्ट्राग्राम में युवको के द्वारा डाले गए वीडियो के बाद काफी फेमस हुई। जहां कुछ दिन पहले नहाने गए जगदलपुर के टीम युवक बह गए थे। जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर रात 12 बजे सही सलामत निकाला था।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान डीएफओ चुड़ामनी सिंह गांव के समूह के द्वारा एक जगह पैसा लिया जा रहा है। जबकि एक जगह पर टिकट चेक किया जा रहा है। पर्यटकों को समझाइश दिया जा रहा है। आज निरीक्षण किया जाएगा। खतरे वाले जगह को बंद भी किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री से जिला सतनामी सेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विधायक गुरु खुशवंत साहेब के नेतृत्व में जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल द्वारा समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियो के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री युवराज ढिरहेर, संजीव बंजारे, करण कोसरे, कमल लहरे, गंगा बंजारे तथा ऋषि खरे आदि शामिल थे।

सरस्वती प्रज्ञा सम्मान से अलंकृत किए गए प्रो. संजय द्विवेदी

भोपाल। प्रख्यात मीडिया शिक्षक और

लेखक प्रो.संजय द्विवेदी को सरस्वती प्रज्ञा सम्मान -2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भोपाल स्थित गांधी भवन में निर्दलीय प्रकाशन,जन संगठन दृष्टि की ओर से आयोजित समारोह में पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ पत्रकार श्री विजयदत्त श्रीधर ने प्रदान किया। इस अवसर पर नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के प्रो.विजय कुमार कर्ण, गांधी भवन न्यास के सचिव दयाराम नामदेव, पत्रकार कैलाश आदमी, गांधीवादी विचारक आर के पालीवाल, प्रिंस अभिषेक अज्ञानी विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रो.संजय द्विवेदी भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक हैं। वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रभारी कुलपति भी रह चुके हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में संपादक के रूप में काम किया है। मीडिया और राजनीतिक संदर्भों पर उनकी 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सक्रिय पत्रकार,लेखक और संपादक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रो.द्विवेदी ने कहा हमारा मीडिया पश्चिमी मानकों पर खड़ा है, उसे भारतीय मूल्यों पर आधारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज के सब क्षेत्रों की तरह मीडिया भी औपनिवेशिक विचारों से मुक्त नहीं हो सका है। हमें संचार, संवाद की भारतीय अवधारणा पर काम करते हुए लोक-मंगल को केंद्र में रखना होगा और संचार के भारतीय माडल बनाने होंगे। इसके लिए समाधानपरक पत्रकारिता का विचार प्रासंगिक हो सकता है। कार्यक्रम का संचालन विमल भंडारी ने किया।

पूरे प्रदेश में पटवारियों ने बंद किया काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पटवारीयों ने काम-काज बंद कर दिया है। रायपुर के नया रायपुर के धरना स्थल पर सभी पटवारी धरना दे रहे हैं। पटवारी दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं है। आम लोगों को परेशानी हो रही है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश के पटवारी सोमवार को आंदोलन करने का ऐलान पहले ही कर चुके थे। जिला मुख्यालयों में भी वे धरने पर बैठे हैं। पटवारियों का कहना है कि न कंप्यूटर है न लैपटॉप बिना इंटरनेट ऑनलाइन काम कैसे करें,जितनी परेशानियां है उसे लेकर राजस्व मंत्री को संघ की ओर से पत्र लिखा गया है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि मंत्री के आग्रह पर पटवारी हड़ताल टाल देंगे पर ऐसा हुआ नहीं।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का किया लोकार्पण

रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज

अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान बोड़ला में 48 लाख 42 हजार की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए 6 अतिरिक्त कक्ष भवन का लोकार्पण किया। उपमुख्यमंत्री के साथ विद्यालय की छात्राओं ने खुद अपने हाथों से इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के माध्यम से क्षेत्र की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय एक सुरक्षित और समर्पित वातावरण प्रदान करेगा, जिससे छात्राएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगी। श्री शर्मा ने कहा, यह विद्यालय उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करेगा और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगा। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, और इस विद्यालय का लोकार्पण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय न केवल शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रायपुर दक्षिण विस उपचुनाव पर सुगबुगाहट तेज

■ **विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- कांग्रेस सेटिंग कर बनाएगी प्रत्याशी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दक्षिण विधान सभा में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी सेटिंग वाला रहेगा। कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है। लेकिन दिखाने के लिए सेटिंग करेंगे, किसी नेता को कहेंगे कि ज्यादा अंतर से नहीं हराएगा। इसके अलावा विधायक चंद्राकर ने प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर बयान दिए हैं।

विधायक अजय चंद्राकर ने पटवारी संघ के अनिश्चित कालीन हड़ताल पर कहा कि वे राजस्व मंत्री कह चुके हैं, जो आवश्यक सुधार होगा, वह किया जाएगा। बहुत सारे अधिकारीस, पटवारी और नायक तहसीलदार फिर से प्रतियोजित किए जाएंगे। उनके मांगों की काफी समस्याएं हल हो जाएगी।

बिजली महंगी होने के बाद से विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगी है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। अब कौन सा प्रदर्शन करेंगे, देखने वाली बात है।

कांग्रेस के दो दिवसीय मैराथन बैठक पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस बैठक कर रही है, केवल बैठक करना ही उनका काम रह गया है। अगले 5 साल उन्हें यही करना है, आरोप-प्रत्यारोप और तोड़फोड़ ही करेंगे।

मानसून सत्र के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति न होने पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अब तक के सबसे मजबूत संसदीय कार्य मंत्री खुद मुख्यमंत्री के पास हैं। संसदीय कार्य मंत्री का विभाग है। मुख्यमंत्री सदन के नेता है, वह सब कुछ संभाल सकते हैं।

मुख्यमंत्री के विभागीय समीक्षा बैठक पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह नियमित कार्यक्रम है, राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। कई विभागीय जानकारियां लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कुछ मुद्दे उठाने की बात कही है। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और हमारा काम है जवाब देना।

गृहमंत्री की तरफ से सुझाव के लिए क्यूआर कोड जारी के बाद भी ग्रामीणों पर बढ़ते हमलों को लेकर कांग्रेस के तंज पर विधायक चंद्राकर ने पटलवार करते हुए कहा कि कांग्रेस 15 साल का वनवास काट करके 5 साल सत्ता में आई। लेकिन नक्सलियों के लिए उनके पास कोई नीति नहीं थी। भाजपा सरकार आने के बाद 6 महीने में ऐतिहासिक संख्या में नक्सली एनकाउंटर हुए हैं। नक्सली अपने कोर एरिया में सुरक्षा बलों के घुसने से बौखला गए हैं। मिली भगत के कारण नक्सलियों को क्षति पहुंचती है। तो कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगते हैं, कबूतर की तरह चीं-चीं करने लगते हैं।

प्रदेश में कोयला घोटाले में पूर्व अधिकारियों पर किए गए एसीबी/ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर विधायक चंद्राकर ने कहा कि ईओडब्ल्यू व ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, न्यायालय अपनी कार्रवाई कर रही है। मामला अभी भी न्यायालय में है, इसलिए हमें इस पर बात नहीं करना चाहिए। राजनीतिक लोग भी कुछ अंदर, कुछ बाहर और कुछ फरार हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई हुई है, भूपेश बघेल ने सभी पर एक समान दया की है।

छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेंगे दो नए मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विष्णुदेव साय कैबिनेट में अब तक दो पद खाली है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। इस संबंध में थोडा इंतजार करने को कहा है। मध्यप्रदेश के कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। उन्होंने विधानसभा मानसून सत्र को लेकर कहा कि सब तैयारी है।

सीएम साय ने यह बात रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में शामिल होने के दौरान कही है। भगवान जगन्नात रथयात्रा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। बघेल ने इस दौरान मंत्रिमंडल के खाली पदों चर्चा की। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री की तुरंत नियुक्ति की बात कही है। इस मुलाकात के दौरान पूर्व सीएम ने कई विषयों पर चर्चा की है।

रथयात्रा में शामिल होने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री राम विचार नेताम और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि रायपुर में जगन्नाथ मंदिर में महा प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र स्वामी और माता सुभद्रा का विधिवाद पूजा अर्चना किए हैं। ऐसे अवसर में यहां भारी उत्साह है।

गैरजिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार सख्त

■ **लंबे समय से गायब 66 डॉक्टरों को नोटिस जारी, बर्खास्त करने की तैयारी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गैरजिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने कई दिनों से ड्यूटी से गायब रहने वाले राज्य के 66 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी डॉक्टरों से उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई है। मामले में अनुपस्थित डॉक्टरों की विभागीय जांच होने और आरोप सही पाए जाने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कार्यालय प्रमुख से प्राप्त जानकारी अनुसार आप अपने पदस्थापना स्थल से दिनांक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। ऐसे शासकीय सेवको के विरूद्ध छ।ग। शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3-1/2014/1-3 10.02.2015 में उल्लेख है कि एक माह या उससे अधिक समय तक अनाधिकृत अनुपस्थित को सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधिन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा से व्यवधान माना जावे। ऐसे शासकीय सेवक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे। साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल दीर्घशास्ति के लिये विभागीय जांच संस्थित की जावे। इसका निराकरण अधिकतम 6 माह की समायावधि में कर लिया जावे।

आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जावे। पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें अनुपस्थिति अवधि के संबंध में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के मांग को लेकर की बड़ी घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों को शासकीयकारण करने की घोषणा की है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सीएम साय ने पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ की शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार गजमाला से किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने स्वयं भी 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सचिवों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने सचिवों की प्रशंसा करते हुए उनसे और भी अच्छा कार्य करने का संकल्प लेने की अपील की।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और छोटी सी अवधि में ही मुख्यमंत्री साय द्वारा अनेक घोषणाओं को पूरा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने पंचायत सचिवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक कार्य करने का अनुभव मुख्यमंत्री साय के पास है।

उपमुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि पंचायत सचिवों के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और सरकार की छवि बनती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों के एरियर्स की राशि का भुगतान किया गया और हड़ताल अवधि के 55 दिनों की राशि का भी भुगतान किया गया।

मांगे पूरी नहीं होने पर चुनाव का किया बहिष्कार, पार्षद बैठेंगे धरने पर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक क्षेत्र के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रायपुर के विधानसभा रोड के करीब ऐश्वर्या वीडमील रिसिंडेसी सोसाइटी में करीब 250 लोग रहते हैं, जिन्हें खराब सड़कें, बारिश से जलभराव, बंद स्ट्रीट लाइट और आसामाजिक तत्व युवाओं के द्वारा लूटपाट होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते रहवासियों ने नगर निगम चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है।

बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जोन-9 कमिश्नर संतोष पांडे और पार्षद गोपेश साहू को शिकायत कर चुके है। लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। आने वाले समय में बारिश के चलते जलभराव होगा तो घरों में पानी घुसेगा। इसलिए हमने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है।

सोसाइटी के सदस्य निलेश गोयल ने बताया की सोसायटी की गंभीर समस्याओं को लेकर जोन कमिश्नर को शिकायत की है। लेकिन अब तक इसे सही नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में गड्ढों और टूटी-फूटी सड़कों के कारण यहां से गुजरना बहुत कठिन हो गया है। बरसात के मौसम में यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

दूसरा पिछले कुछ समय से यहां कई स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। रात के समय अंधेरा होने के कारण लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है। और असामाजिक गतिविधियों का भी डर रहता है। तीसरा सीवेज के ब्लॉक होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दुर्गंध के कारण रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है।

रहवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी नगरी निकाय चुनाव में पूरी तरीके से चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है।

वहीं इस मामले को लेकर पार्षद गोपेश साहू ने कहा की जोन 9 के अधिकारियों की वजह से यह पूरा काम रुका हुआ है। आज यही सब समस्याओं को लेकर मैं दोपहर 1 बजे प्रदर्शन पर बैठूंगा। मैं अकेले इस प्रदर्शन पर बैठूंगा। कई बार स्ट्रीट लाइट, सड़कों के मामले को लेकर भी मैं शिकायत की है। कई काम रूके हुई हैं। लेकिन वह लोग काम नहीं कर रहे हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ आज में जोन 9 कमिश्नर संतोष पांडे सहित के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठूंगा। जिससे आम जनता की समस्या का निराकरण हो सके।

शहरों के विकास के लिए नहीं होगी राशि की कमी : अरुण साव

■ **उप मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए लागत के 94 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन**

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपए के 94 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया। बिलासपुर के जिला खेल परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने की। उप मुख्यमंत्री श्री साव की पहल और विधायक श्री शुक्ला के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग, अधोसंरचना मद एवं निकाय मद के अंतर्गत ये विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अधिकांश स्वीकृत कार्य सीसी रोड, नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट से संबंधित हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव एवं विधायक श्री शुक्ला ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत खेल परिसर में नीम के पौधे भी लगाए।

भूमिपूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि विगत पांच सालों में पहली बार विकास कार्यों के लिए लगभग 15 करोड़ की एकमुश्त राशि मिली है। हमारी सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है।

शहरों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। जनभावना के अनुरूप तमाम विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से हाल ही में मुलाकात हुई है। हमें जल्द ही और आबंटन मिलने की संभावना है। इससे हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति को रहने के लिए पक्का छत मिल सकेगा। उन्होंने %एक पेड़ मां के नाम% अभियान के तहत सभी को पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने इसे बड़े होते तक सहेजने को भी कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव शहर की समस्याओं से अवगत हैं। धीरे-धीरे पूरी समस्याओं का समाधान होगा। इससे शहर की दशा एवं दिशा जरूर बदलेगी। नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने कार्यक्रम में स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई की बढ़ी मुश्किलें

■ **ईओडब्ल्यू और एसीबी ने फिर दर्ज किया केस**

रायपुर। कोयला घोटाला केस में निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तीनों अधिकारियों के खिलाफ फिर एक बार ईओडब्ल्यू और एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। तीनों अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग मामला दर्ज हुआ है, जिसमें धारा 22, 23 और 24 है।

ईओडब्ल्यू और एसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति है। वहीं रानू साहू पर साल 2015 से लेकर 2022 तक करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खुद के नाम से है। इसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों के नाम से संपत्ति खरीदने का आरोप है। जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक कुल वेतन 92 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई के पास साल 2010 से लेकर 2022 तक कुल वेतन 93 लाख रुपए है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से 5 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्ति खरीदी है, जो कि उनके वेतन से लगभग 5 गुना अधिक है।

छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला, लेवी वसूली का केस प्रवर्तन निदेशालय की रेड में सामने आया था। कोयला परिवहन में कोल व्यापारियों से कोल वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था। इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी। इस पूरे केस का मास्टरमाइंड और किंगपिन कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जो 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम जमा कराता था। इस तरह से कोयला घोटाला मामले में लगभग 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। कोयला घोटाला केस में निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया जेल में बंद है।

रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के दो बड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। बता दें कि रानू साहू लंबे समय से जेल में बंद है। इस मामले में बचाव पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल की डबल बैंच ने अंतरिम जमानत का आदेश जारी किया। बता दें कि ईडी ने जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लंबे समय से जेल में बंद रानू साहू के खिलाफ एसीबी-ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज किया है। निलंबित आईएएस रानू साहू पर वर्ष 2015 से 2022 तक करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति स्वयं के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप है।

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

निविदा सूचना

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोनाखान के संचालन हेतु सत्र 2024-25 (जुलाई 2024 से जून 2025) हेतु पंजीकृत फर्मों/आपूर्ति कर्ताओ से सील बंद निविदाए आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का नाम	अमानत राशि
1	2	3
1	खाद्य सामाग्री	60000
2	सब्जी	12000
3	फल	7000
4	मांसाहारी	5000
5	बेकरी एण्ड स्वीटस	5000
6	लेखन सामग्री	10000
7	बिछावन सामग्री	10000
8	दैनिक उपयोग की सामग्री	5600
9	हेयर कटिंग	4000
10	एन.सी.ई.आर.टी. बुक	3000

निविदा फार्म एवं अन्य जानकारी सहित सामग्री सूची संबंधित एकलव्य जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान (सहायक आयुक्त कार्यालय) समिति कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में दिनांक **05.07.2024** से **12.07.2024** तक प्रात: 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक रू. 500/- के नगद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

पूर्ण रूपेण भरी हुई मुहरबंद निविदा समिति कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास बलौदाबाजार-भाटापारा में दिनांक **18.07.2024** दोपहर 2:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदा लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा समिति कार्यालय में रखे टेन्डर बाक्स में जमा कराया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं दिनांक **19.07.2024** को शाम 3:00 बजे कार्यालय के कक्ष कमांक 87 में क्रय समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा। निविदा का पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित है अमानत राशि केवल डिमाड ड्राफट के रूप में ही स्वीकार की जावेगी। सब्जी-फल, बेकरी, अण्डा-चिकन, प्रेस, बालकटिंग, एन.सी.ई.आर.टी. बुक हेतु जीएसटी, टिन नम्बर अनिवार्य नही है। निविदा फार्म में दर्शायी गयी सूची के अनुसार नमूना (Sample) निविदाकर्ता द्वारा निवदा खोलते समय किन्तु जीएसटी वाले फार्म है उनके क्रय हेतु प्राथमिकता प्रदाय की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जी-242500924/4 आदिवासी विकास जिला बलौदाबाजार-भाटापारा

क्या ईरान की सियासत बदल देंगे नए राष्ट्रपति

अभिनय आकाश

ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मई महीने में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। ईरान के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे पेजेशकियान की बात करें तो वो पेशे से हार्ट सर्जन रहे हैं। वो पांच बार ईरान की संसद में पहुंचे हैं और एक बार संसद के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। 69 साल के सुधारवादी नेता माने जाने वाले पेजेशकियान मोरल पुलिसिंग के कड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने ईरान में एकता और सदभाव लाने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो दुनिया से ईरान के अलगाव को खत्म करेंगे। ऐसे में क्या क्या ईरान की सियासत बदल देंगे नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान? ईरान में आए इस बदलाव से भारत के साथ रिश्तों पर क्या होगा असर? पज़शकियान का जन्म 29 सितंबर, 1954 को उत्तर-पश्चिमी ईरान के महाबाद में हुआ था। पेजेशकियान के पिता जातीय रूप से अज़ेरी थे और उनकी माँ कुर्दिश थीं। वह अज़ेरी भाषा बोलते हैं और उन्होंने लंबे समय से ईरान के विशाल अल्पसंख्यक जातीय समूहों के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है। 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान, पेज़ेशकियान, एक लड़ाकू और चिकित्सक, को चिकित्सा टीमों को अग्रिम पंक्ति में तैनात करने का काम सौंपा गया था। इसके बाद वह हृदय सर्जन बन गए और ताब्रीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रमुख के रूप में कार्य किया। हालाँकि, 1994 में एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी फ़तेमेह मजीदी और एक बेटी की मृत्यु के बाद व्यक्तिगत त्रासदी ने उनके जीवन को आकार दिया। डॉक्टर ने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपने बाकी दो बेटों और एक बेटी को अकेले ही पाला। पेज़ेशकियान ने पहले देश के उप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और बाद में सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के प्रशासन में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। पेज़ेशकियान ने 2001 से 2005 तक खातमी के दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 2006 में पेज़ेशकियान को तबरीज़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक लॉ मेकर के रूप में चुना गया था। बाद में उन्होंने डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर के रूप में कार्य किया और सुधारवादी और उदारवादी कारणों का समर्थन कियामसूद पेजेशकियन का झुकाव पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी की ओर है, जिनके शासन के तहत तेहरान ने विश्व शक्तियों के साथ 2015 का ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था। हालांकि, यह परमाणु समझौता रद्द हो गया था और कट्टरपंथी नेता दोबारा सत्ता पर काबिज हो गये थे। हृदय रोग विशेषज्ञ मसूद फिर से परमाणु समझौता करने और पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर करने के पक्षधर हैं। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। पेज़ेशकियान की अध्यक्षता में इन संबंधों के और गहरे होने की संभावना है। फोकस विशेष रूप से रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर होगा। ये एक परियोजना जिस पर भारत पहले ही भारी निवेश कर चुका है। यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। भारत ने शाहिद-बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए .120 मिलियन का वादा किया है और ईरान में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन की क्रेडिट लाइन की पेशकश की है। ऐसे में जो भी सत्ता संभाले विशेषज्ञों का मानना ??है कि ईरान की सामान्य विदेश नीति में बदलाव की संभावना नहीं है। हालाँकि, कार्यप्रणाली और विवरण भिन्न हो सकते हैं। ईरान भारत के कच्चे तेल के प्रमुख स्रोतों में से एक है। ईरान द्वारा जारी पश्चिमी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में तेल के निर्यात में वृद्धि पर नजर रखने के साथ ही भारत कच्चे तेल के एक विश्वसनीय और यकीनन सस्ते स्रोत पर विचार कर सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए पेज़ेशकियान दृष्टिकोण पर नई दिल्ली में बारीकी से नजर रखी जाएगी। इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी को बनाए रखने और जिसे वह ज़ायोनी शासन कहते हैं, उसके खिलाफ रणनीतिक क्षेत्रीय पक्ष रखने से संबंधित उनका रुख इस क्षेत्र में भारत की कड़ी कूटनीति को प्रभावित करना जारी रख सकता है। भारत और ईरान के बीच घनिष्ठ सहयोग का एक अन्य मंच अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) है।

ब्रिटेन में सुनक की हार के मायने

कमलेश पांडे

ब्रिटेन में पीएम कीर स्टार्मर के नेतृत्व में लेबर पार्टी 14 साल के लंबे इंतजार के बाद गत 6 जुलाई शुक्रवार को वहां सत्ता में आई और कीर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त दी है। उल्लेखनीय है कि 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के 412 सांसद जीते हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के महज 121 सांसद। लेकिन वहां की सियासत में यह नौबत क्यों और कैसे आई, इसके सियासी मायने साफ हैं, जिसे जानने की दिलचस्पी ब्रिटिशर्स के अलावा भारतीयों में भी है। इसलिए इस बात की विस्तृत चर्चा हमलोग आगे देखेंगे।

ब्रिटिश सत्ता में भारतीयों की दिलचस्पी भला हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ऋषि सुनक के पीएम बनते ही हिंदूवादियों ने उन्हें गौ-भक्त और मंदिर प्रेमी ठहरा दिया। लोगों ने यहां तक कहा कि जिस मुल्क ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, आज वहां का शासक एक भारतीय मूल का व्यक्ति बतौर पीएम बन चुका है। वहीं, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच के संवाद और जारी फोटोग्राफ भी बिना कुछ कहे सभी कुछ बतला गए।

इसी कड़ी में भारत में जो कुछ भी कहा और बोला, उसे ब्रिटिश लोग भी बड़े ही ध्यान से सुन-समझ रहे थे और जब अगली बार चुनाव की नौबत आई तो अपना निर्णय सुना दिया और भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यक्ति ऋषि सुनक को सत्ता से बाहर करते हुए ब्रिटिश मूल के अंग्रेज कीर स्टार्मर के हाथों अपनी बागडोर सौंप दी। यह तो महज एक कारण हुआ। लेकिन ऋषि सुनक के भारी पराजय की स्थिति वहां की आर्थिक बदहाली और अनवरत सत्ता संघर्ष में भी दृष्टिगोचर होते हैं।

सच कहूं तो ब्रिटेन इन दिनों कई संकटों का सामना कर रहा है। इसका सबसे जीता-जागता उदाहरण वहां की अर्थव्यवस्था है, जिसमें वर्ष 2023 में महज 0.1 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2024 की शुरुआत में ही मंदी आ गई, जिससे वहां पर जीवन-यापन करना मुश्किल हो चुका है। आंकड़े चुगली कर रहे हैं कि अक्टूबर 2022 में महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। भले ही पीएम सुनक के उपायों से हाल ही में महंगाई में कमी आई है, लेकिन महंगाई डायन ने लोगों को नाराज कर दिया, जिससे ऋषि सुनक को नजर लग गई और उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा।

कहा तो यहां तक जा रहा है कि ब्रिटेन में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस के समक्ष फंड का संकट उतपन्न हो चुका है। आम नागरिकों को समय पर और सस्ती मेडिकल सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया है। वहीं, आप्रवासन विशेषकर तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान से शरण की तलाश में ब्रिटेन आने वाले लोगों ने पश्चिमी देश की चिंता बढ़ा दी है। यह देश के लिए एक गम्भीर मुद्दा है, जिसका दोष कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक पर ही गया।

ब्रिटेन की जनता के बड़े हिस्से का दो टूक मानना है कि सरकार स्वास्थ्य और रक्षा से लेकर आव्रजन और अर्थव्यवस्था तक लगभग हर बड़े मुद्दे संभालने में विफल साबित हुई है। वहीं, बीते कुछ वर्षों में कंजर्वेटिव पार्टी विभाजित होती दिखाई पड़ी, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई और इसकी कीमत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को अपनी सत्ता गंवा कर चुकानी पड़ी।

समझा जाता है कि यूरोपीय संघ से बाहर होने का ब्रिटेन का फैसला कई मामलों में उसपर भारी पड़ रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर भी पुनर्विचार की जरूरत महसूस की जा रही है।

वहीं, दूसरी ओर लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर भारत से नई रणनीतिक साझेदारी के पक्षधर रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिला। आंकड़े बता रहे हैं कि लेबर पार्टी से भारतीय मूल के सबसे ज्यादा 17 सांसद, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी से महज 3 सांसद और लिबरल डेमोक्रेट्स से सिर्फ 1 सांसद चुने गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सियासी एक्सपर्ट की राय है कि कीर स्टार्मर ने भारतीय मूल के लोगों के साथ लेबर पार्टी के सम्बन्धों में सकारात्मक बदलाव की वकालत की है, जिसका सीधा फायदा उन्हें मिला। वहीं, भारतीय राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि भारतीय सत्ता पक्ष यानी भाजपा से प्रेरित होकर तत्कालीन ब्रिटिश विपक्ष लेबर पार्टी ने 400 पार का जो नारा गढ़ा, उसने उसे सत्ता तक पहुंचा दिया, जबकि इसके स्वप्नद्रष्टा पीएम नरेंद्र मोदी गठबंधन की बैशाखियों पर निर्भर हो गए।

इतना ही नहीं, स्टार्मर ने लेबर पार्टी को जनादेश मिलने पर भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) समेत नई रणनीतिक साझेदारी का संकल्प जताया था, जो ब्रिटिशर्स को रास आ गई। बता दें कि लेबर पार्टी ब्रिटिश भारतीयों के साथ अपनी पार्टी के रिश्ते को नए सिरे से आकार देने में जुटी है, जो पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन के कार्यकाल में कश्मीर पर कथित भारत विरोधी रुख को लेकर प्रभावित हुए थे।

उल्लेखनीय है कि बीते साढ़े 4 साल तक पार्टी में जो बदलाव किए गए, उसका यही मकसद है कि एक बदली हुई लेबर पार्टी देश सेवा के लिए तैयार हो चुकी है और जनता ने भी उसे एक नया मौका दे दिया है। ऐसा इसलिए कि ब्रिटेन को कामकाजी लोगों की सेवा में फिर से लगाने को लेबर पार्टी तैयार है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि दिसंबर 2019 में करारी चुनावी हार के बाद लेबर पार्टी की किस्मत में प्रभावशाली और विजयी उलटफेर के लिए जो अद्भुत व अकल्पनीय प्रयास किये गए, उसका श्रेय अब स्वाभाविक रूप में कीर स्टार्मर के खाते में ही जायेगा। बता दें कि हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 सीटों में से लेबर पार्टी को 412 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी महज 121 सीटों पर सिमट चुकी है। हालांकि सुकून की बात यह है कि भारतवंशी सांसदों की संख्या में वहां पर लगभग दुगुना इजाफा हुआ है, जो 15 से बढ़कर 27 तक पहुंच चुके हैं।

एकात्मता के स्वर

नवग्रह

विशाल आकाश में नै ग्रह करो गये हैं। यथा- सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, गुरु, राहु और केतु। सूर्य में सुपुग्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विध्वव्यचा, संयद्वसु, अर्वावसु तथा स्वराडू ये सात रश्मियाँ कही गयी हैं।

माघ में सूर्य का नाम वरुण, फाल्गुन में पूषा, चैत्र में अंश, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इन्द्र, आषाढ़ में सविता, श्रावण में विवश्यान, भाद्रपद में भ1, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीष में मित्र और पीष में सनातन विष्णु कहलाते है। सूर्य वर्ष में प्रतिमाह राशि को बदलते हुए बारह राशियों पर घूमते हैं। उनके रथ में सात घोडे जुते हैं। अरुण उनके सारथी है। सूर्य के प्रभाव से सभी नक्षत्र एवं तारे नित्य बढ़ते हैं। चन्द्रमा का रथ तीन चक्रों वाला है। उसके वाम और दक्षिण भाग में कुन्द पुष्प के समान वर्ष वाले दस अश्व जुते हैं। शुक्ल के पंद्रह दिन अपनी कलाओं का विस्तार करते हैं व कृष्णपण में वह क्षीण होती है।

सुषुम्न नामक सूर्य की रश्मि चन्द्रमा की चाँदनी को पुष्ट करती है। पूर्णिम की पूर्ण चाँदनी देख समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। समुद्र ही इनके जन्मदाता हैं। मंगल आठ घोड़ों से युक्त रहने वाला मंगल का स्वर्णमय रथ है। सूर्य की संयद्वसु नाम से प्रसिद्ध रश्मि मंगल का नित्य पोषण करती है। बुध के रथ में जल से उत्पन्न वेगवान आठ घोडे जुते हुए है वह उसी रथ से सर्वत्र गमन करते हैं। सूर्य की विश्वकर्मा नामक रश्मि सदा पोषण करती है। बृहस्पति का भी आठ घोडों से युक्त रथ स्वर्ण निर्मित है। सूर्य की अर्वावसु नामक रश्मि बृहस्पति का पोषण करती है। शुक्र का रथ भूमि से उत्पन्न दस घोडों द्वारा धारण किया जाता है। सूर्य की विश्वव्यचा नाम की जो रश्मि है, वह नित्य शुक्र ग्रह का पोषण करती है।

लोहे से बने शनि के दिव्य रथ को आठ घोडे वहन करते हैं। सूर्य की स्वराड् नामक रश्मि उनका पोषण करती है। राहु का रथ छह घोडों से युक्त है। केतु का रथ भी छह सुन्दर घोडों से युक्त है। इस प्रकार सभी ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में रहकर सृष्टि का संचालन करते हैं। भूमि से एक लाख योजन ऊपर सूर्य का मण्डल स्थित है। वहाँ से भी एक लाख योजन ऊपर चन्द्रमा का मण्डल कहा गया है। नक्षत्रमण्डल से उत्तर दो लाख योजन की दूरी पर बुध है। बुध से उतने ही प्रमाण की दूरी पर शुक स्थित है।

शुक से उतने ही प्रमाण पर मंगल की स्थिति है। मंगल से दो लाख योजन की दूरी पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। बृहस्पति से भी दो लाख योजन की दूरी पर सूर्य पुत्र शनैश्चर स्थित हैं। ग्रहों के मण्डल से एक लाख योजन की दूरी पर सप्तर्षि मण्डल प्रकाशित है और वहाँ से भी एक लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित है जो संपूर्ण ज्योतिश्चक का केन्द्र रूप है।

पुराण दिग्दर्शन ....

पुराण-परिचयाध्याय

किसी पदार्थ के निर्णय में उसका नाम भी गुण अथवा अवगुण बताने का एक साधन माना जाता है। प्राचीन काल से यह प्रथा चली आती है कि किसी भी पदार्थ-विशेष का वैसा ही नामकरण-संस्कार किया जाय जो कि अधिक से अधिक सीमा तक उसके गुण और अवगुणों को प्रकट करने की शक्ति रखता हो।

ग्रन्थ लेखक एवं कवि अपने निबन्धों का नाम धुनने में बहुत सोच विचार किया करते हैं और चाहा करते हैं कि ग्रन्थ का विस्तृत प्रतिपाद्य विषय हमारे निर्वाचित (कम से कम अक्षरों वाले) नाम से अभिव्यक्त हो सके। शायद विज्ञ पाठकों को यह बताने की आवश्यकता न हो कि हमारे संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थकारों को नाम चुनने में प्रायः सफलता मिली है। जहाँ वेद, उपनिषद्, स्मृति और पुराण आदि नाम अपने 2 प्रतिपाद्य विषयों को स्पष्टतया घोषित कर देते हैं तथा उक्त शब्दों के निर्वचनमात्र जान लेने से मूल ग्रन्थों का भान हो जाता है, वहाँ रघुवंश, कुमार-संभव, मुद्रा-राक्षस आदि आधुनिक ग्रन्थ भी इसी शैली का अनुसरण करते हुए अपने 2 प्रतिपाद्यविषयों का पता देते हैं यही क्यों? हमारे पूर्वजों ने इस नामकरण-शैली की प्रथा को ऐसा सुव्यवस्थित बनाने की चेष्टा की थी कि जिसे ध्यानपूर्वक देखने पर चकित सा रहना पड़ता है। रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में नायक प्रतिनायक तथा अन्यान्य मुख्य पात्रों तक के नाम ऐसे विलक्षण हैं कि जो उस 2 व्यक्ति के चरित्रों को विशेषता को सहसा प्रकट कर देते हैं। राम जहां मर्यादाओं के आदर्शपालक होने के कारण प्रत्येक प्राणी के चित में रमण करने वाले थे, वहां रावण भी अपने अन्वर्थ गुण में कम न था। अर्थात् - प्राणीमात्र का सर्वोपरि रुलाने वाला था। युधिष्ठिर- को महाभारत के युद्ध में स्थिर होना पड़ा और उन्होंने अपनी इस स्थिरता को अनेक धर्म-संकटों के अवसरों में भी हाथ से न जाने दिया।

क्रमशः ...

जीवन के तड़प को पर्दे पर महसूस कराने वाला अभिनेता गुरुदत्त

प्रदीप सिंह

भारतीय सिनेमा पर कोई भी बात गुरु दत्त के बिना अधूरी है। मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा की सीमाओं के भीतर काम करते हुए, उनकी संवेदनाएं समृद्ध, आधुनिक और सूक्ष्म थीं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक प्यासा टाइम पत्रिका की ऑल-टाइम 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल है। उनका अभिनय और फिल्म ठुकराये जाने के दुख और दर्द से भरा है। प्यासा और कागज के फूल दोनों ने एक संवेदनशील व्यक्ति के समाज से मोहभंग की कहानी है। गुरुदत्त ने जीवन में कभी भी दुख की तस्वीर को इस तरह से नहीं हटाया। प्यासा और कागज के फूल के बाद की फिल्मों, चौदहवीं का चाँद और साहिब बीबी और गुलाम के साथ अपने बहुत से पैसे वसूल किए। गुरु दत्त ने पहले कॉमेडी और थ्रिलर के साथ एक सफल प्रदर्शन किया था - आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, बाजी और सीआईडी- सभी ने गुरु दत्त को एक अभिनेता-निर्देशक या एक निर्माता के रूप में देखा।

गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई, 1925 को कर्नाटक के बेंगलुरू में हुआ था। माता-पिता ने उनका नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण रखा। उनके माता-पिता कर्नाटक के कर्वार नामक स्थान के रहने वाले थे। लेकिन बाद में वह भवानीपुर, पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने बचपन की एक दुर्घटना के कारण अपना नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से बदलकर गुरु दत्त रख लिया था।

गुरु दत्त को बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का भी श्रेय दिया जाता है-उन्होंने वहीदा रहमान को फिल्मों में आगे बढ़ाया, बदरुद्दीन काज़ी (जिन्हें जॉनी वॉकर कहा जाता है), लेखक-निर्देशक अबरार अल्वी और प्रसिद्ध छायाकार, वीके मूर्ति जैसी प्रतिभाओं की खोज की।

हालाँकि, कई लोगों की राय है कि गुरु दत्त कभी भी विफलता और अस्वीकृति को पचा नहीं सकते थे। गुरुदत्त का निजी जीवन भी उथल-पुथल भरा रहा। उनकी बहन, चित्रकार ललिता लाजमी (दिवंगत फिल्म निर्माता कल्पना लाजमी की मां) के अनुसार, गुरुदत्त-गीता दत्त की शादी बहुत सफल नहीं थी। दोनों संवेदनशील आत्माएं थीं - न तो वे एक दूसरे के साथ रह सकते थे और न ही एक दूसरे के बिना। जबकि कई लोग वहीदा की उपस्थिति को गुरु दत्त और गीता दत्त के बीच विवाद का कारण मानते हैं, ललिता इसका जोरदार खंडन करती हैं। वह इस बात से सहमत है कि वहीदा उसके भाई के साथ काम करती थी। लेकिन उसके साथ उनकी शादी में आने वाली परेशानी के बारे में बताना गलत होगा।

ललिता ने फिल्मफेयर के एक लेख में संपादक फरहाना फारूक से बात करते हुए कहा कि गीता एक बहुत प्यारी व्यक्ति थी, स्वभाव से पजेसिव थी और गुरु दत्त पर संदेह करती थी कि उनके साथ काम करने वाली हर अभिनेत्री के साथ उनका संबंध है। गीता के साथ समस्या यह थी कि वह बेहद स्वामित्व वाली थी। यह भावना किसी भी शादी को चलने में समस्या पैदा कर सकती है। एक निर्देशक/अभिनेता जैसा रचनात्मक व्यक्ति कई अभिनेत्रियों के साथ काम करता है।

संसद में विपक्ष मजबूत, सरकार पर खतरा नहीं

पी. चिदंबरम

संसद सत्र के पहले नियमित कार्य दिवसों ने मेरे संदेह की पुष्टि की है। जाहिर है, जहां तक नरेंद्र मोदी की सरकार का सवाल है, संसद के अंदर केवल कुछ दृश्यों के अलावा कुछ भी नहीं बदला है। यह स्पष्ट है कि मोदी ने पूरी दृढ़ता से इस बात का निर्णय कर लिया है कि चुनाव से पहले किए गए दावों और नीतियों पर ही आगे बढ़ा जाएगा। विडंबना यह है कि संसद के दोनों सदनों में मोदी के इसी विचार पर अमल किया जा रहा है।

परंपरा तो यह है कि संसद के दोनों सदन सर्वसम्मति से चलते हैं, न कि सत्तापक्ष के बहुमत से। एक बहुत ही छोटे से प्रश्न से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि 'हमें बिना भोजनावकाश के संसद की कार्यवाही जारी रखनी चाहिए?' इस बात का निर्णय पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति या सदन के बहुमत से नहीं, बल्कि सर्वसम्मति से होना चाहिए। फिर भी दोनों पीठासीन पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के खिलाफ चर्चा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बहुत ही दुख की बात है कि यह पिछली सरकार के पांच सालों की याद दिला रहा है।

संसद के दोनों सदनों में पहली बहस और संसद के बाहर लिए गए फैसलों ने सरकार की मंशा और दिशा को स्पष्ट कर दिया है कि देश सिर्फ एक व्यक्ति के आदेशों पर चलेगा। सदन में दो महत्वपूर्ण घटक (टीडीपी और जेडीयू) के अलावा अन्य छोटे दलों का काम सिर्फ सदन की मेज थपथपाना है। मोदी अपने मंत्रियों या दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं को

कोई मौका नहीं देंगे। अपनी सरकार की सभी गलतियों का ठीकरा जवाहरलाल नेहरू से शुरू कर बाद की कुछ अन्य सरकारों पर फोड़ा जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता ट्रोल्स को लेकर बेहद आक्रामक रहेंगे। उन जांच एजेंसियों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, जो सरकार के इशारे पर काम करती हैं और उनका काम जारी रहेगा। स्पष्ट रूप से 543 सांसदों वाली लोकसभा में भाजपा के 240 या एनडीए के 292 सांसद मिलकर भी मोदी को नहीं रोक पाए तो बाकी के सांसदों का क्या है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चार दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन ये शुरुआती संकेत हैं।

महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भाजपा या एनडीए के सांसद बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत जल्द राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन्हें स्थिति और खराब होने का अंदेशा है। महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार का धीरे-धीरे पतन, हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के बीच बराबरी का मुकाबला, इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को जमानत देने के फैसले ने इन तीनों राज्यों में इंडी गठबंधन में एक नई जान फूंक दी है। एनडीए/भाजपा को पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड और कर्नाटक में हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहां अभी चुनाव नहीं होने वाले हैं।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के एनडीए/भाजपा सांसदों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान तो थी, लेकिन वे 'गठबंधन' वाले टैग की वजह से शर्मिंदा हैं। उन्हें इस बात का भी अंदेशा है कि यह गठबंधन लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं?

भाजपा इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अजेय पार्टी होने का दावा करने से पहले उसे एक बड़ा पहाड़ चढ़ना है। उसी तरह कांग्रेस को भी भाजपा से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है। मैं इस बात को बता सकता हूं कि कांग्रेस ने नौ राज्यों में अपनी अधिकतर सीटें जीती हैं, लेकिन 170 सीटों वाले 9 राज्यों में कांग्रेस ने मात्र 4 सीटें जीतीं, जबकि 215 सीटों पर खुद न लड़कर उसने अपने सहयोगियों को उतारा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर है, लेकिन वे सरकार को हराने की स्थिति में नहीं हैं। राजसत्ता की चाबी टीडीपी(16) और जेडीयू (12) के हाथों में है। दोनों ही पार्टियां बजट का इंतजार करने के साथ विशेष दर्जा की मांग करते रहेंगे, जबकि उन्हें भी पता है कि मोदी यह नहीं देने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों को महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार रहेगा।

अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों का आर्थिक नीतियों से क्या लेना-देना है? मैं कुछ चिंताजनक अनुमान लगा सकता हूं- सरकार इन्कार की मुद्रा में बनी रहेगी। वह बढ़ती बेरोजगारी, विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत और निचले तबके में व्याप्त गरीबी और असमानता की बात से भी इन्कार करती रहेगी। ऐसे में मौजूदा आर्थिक नीतियों में कोई आमूलचूल बदलाव नहीं होगा। सरकार बुनियादी ढांचे और वैनिटी परियोजनाओं में निवेश करना जारी रखेगी। हालांकि बुनियादी ढांचे पर सरकारी व्यय के आर्थिक लाभ हैं, निजी निवेश नहीं होगा और विकास दर मध्यम रहेगी। घालमेल वाले आंकड़ों से इसका बचाव किया जाएगा।

सरकार चाइबोल के नेतृत्व वाले विकास के दक्षिण कोरिया मॉडल का पालन करना जारी रखेगी। प्रमुख क्षेत्रों में एकाधिकार और अल्पाधिकार पनपेंगे। नतीजतन, छोटे और मझोले उद्योगों की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। नए रोजगार का सृजन सुस्त रहेगा। कम पढ़े-लिखे और लाखों की तादाद में हर साल तैयार होने वाले अकुशल युवाओं को सबसे ज्यादा तनाव झेलना होगा। एक बढ़ती उम्र वाले नेता के नेतृत्व में सरकार का तीसरा कार्यकाल उन प्रतिभाओं को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं वानिकी, विज्ञान एवं अनुसंधान और विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए गए अपने भाषणों में जितने वादे किए हैं, वे उन्हीं में विश्वास रखते हैं। इसलिए इस तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहें।

आज का इतिहास

1868 संयुक्त राज्य संविधान के चौदहवें संशोधन को स्वीकृति दी गई।
1877 पहली विंबल्डन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
1877 उद्घाटन विंबलडन चैंपियनशिप, जो दुनिया का सबसे पुराना टेनिस्टॉर टूर्नामेंट है, खुल गया।
1896 राजनेता विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने अपने क्रॉस ऑफ़ गोल्ड स्पेकहैडोवेटिंग बाईमेटालिज़्म को बनाया, जो अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राजनीतिक चेहरों में से एक माना जाता है।
1900 क्वीन विक्टोरिया ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान की पुष्टि करते हुए, यूनाइटेड किंगडम की संसद के एक अधिनियम को अपनी रॉयल असेंटेंट दिया।
1903 जोसेफ स्टालिन को साइबेरिया में निर्वासित किया गया था। जोसेफ स्टालिन बाद में सोवियत संघ के नेता बने। वह एक समाजवादी थे।
1922 जॉनी वीस्मुल्लर ने 58.6 सेकेंड में 100 मीटर की फ्रीस्टाइल तैराई, जिससे एक विश्व तैराकी रिकॉर्ड और द वर्ल्ड बैरियर टूट गया।
1932 ब्राजील की संघीय सरकार ने साओ पाउलो राज्य को विद्रोह कर दिया था। इसने ब्राजील में संवैधानिक क्रांति की शुरुआत की।
1943 सिसिली पर संबद्ध बलों द्वारा एक शानदार हमला किया गया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हस्की के नाम से जाना जाता था।
1944 ब्रिटेन और कनाडा के बलों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के एक शहर केन पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के आक्रमण के बाद शहर को नाजी जर्मनों द्वारा नियंत्रित किया गया था। लड़ाई को नॉरमैंडी की लड़ाई के रूप में जाना जाता था।
1944 Saipan को अमेरिका द्वारा नियंत्रण में लिया गया था। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटी। मरीना द्वीप समूहों के साइपन द्वीप पर जापानी सेना ने कब्जा कर लिया था।

मध्यवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान की जानी चाहिए बजट में

प्रह्लाद सबनानी

जुलाई 2024 माह में शीघ्र ही केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक बजट पेश किया जाने वाला है। हाल ही में लोक सभा के लिए चुनाव भी सम्पन्न हुए हैं एवं भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुन: सौंप दी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। अब केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शीघ्र ही केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं।

पिछले लगातार दो वर्षों के बजट में पूंजीगत खर्चों की ओर इस सरकार का विशेष ध्यान रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया गया था और वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस राशि में 33 प्रतिशत की राशि की भारी भरकम वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 11 प्रतिशत ही अधिक है। इस राशि को यदि 33 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया जा सकता है तो इसे कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे बढ़ाने के प्रयास होना चाहिए अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि के स्थान पर 12.5 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया जाना चाहिए।

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए पूंजीगत खर्चों में वृद्धि होना बहुत आवश्यक है और फिर भारत ने तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर की रफ्तार को पकड़ा ही है। आर्थिक विकास की इस वृद्धि दर को बनाए रखने एवं इसे और अधिक आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्चों में वृद्धि करना ही चाहिए। आर्थिक विकास दर में तेजी के चलते देश में रोजगार के नए अवसर भी अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को बहुत अधिक आवश्यकता भी है। भारत में पिछले 10 वर्षों के दौरान विकास की दर को तेज करने के चलते ही लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के ऊपर उठ पाए हैं एवं करोड़ों नागरिक मध्यवर्ग की श्रेणी में शामिल हुए हैं। अब भारत में गरीबी की दर 8.5 प्रतिशत रह गई है

जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में 21.1 प्रतिशत थी। गरीबी की रेखा से बाहर आए इन नागरिकों एवं मध्यवर्गीय नागरिकों ने देश में उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, कर संग्रहण में भी इस वर्ग ने महती भूमिका अदा की है। आज प्रत्यक्ष कर संग्रहण लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है तथा वस्तु एवं सेवा कर भी अब औसतन लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह से अधिक की राशि के संग्रहण के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि का लाभांश केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया है तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित कर केंद्र सरकार को भारी भरकम राशि का लाभांश उपलब्ध कराया है, जबकि कुछ वर्ष पूर्व तक केंद्र सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के घाटे की आपूर्ति हेतु इन बैंकों को बजट में से भारी भरकम राशि उपलब्ध करानी होती थी। कुल मिलाकर इस आमूल चूल परिवर्तन से केंद्र सरकार के बजटीय घाटे में भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है। केंद्र सरकार का बजटीय घाटा कोविड महामारी के दौरान 8 प्रतिशत से अधिक हो गया था जो अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 5.1 प्रतिशत तक नीचे आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार, अब यह सिद्ध हो रहा है कि केंद्र सरकार ने न केवल अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने में सफलता अर्जित की है बल्कि अपने खर्चों को भी नियंत्रित करने में सफलता पाई है।

पूंजीगत खर्चों में वृद्धि के साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में मध्यवर्गीय नागरिकों को आय कर की राशि में छूट देने का प्रयास भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में किया जाना चाहिए। क्योंकि, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में हो रही भारी भरकम 25 प्रतिशत की वृद्धि इसी वर्ग के प्रयासों के चलते सम्भव हो पा रही है। वैसे, भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार भी नागरिकों/करदाताओं पर करों का बोझ केवल उतना ही होना चाहिए जितना एक मधुमक्खी किसी फूल से शहद लेती है। मध्यवर्गीय नागरिकों के हाथों में अधिक राशि पहुंचने का सीधा सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को ही होता है। मध्यवर्गीय नागरिकों के हाथों में यदि खर्च करने के लिए अधिक राशि पहुंचती है तो वह विभिन्न उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता है इससे इन उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होती है और इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर अर्थव्यवस्था में निर्मित होते हैं एवं कम्पनियों द्वारा विनिर्माण इकाईयों का विस्तार किया जाता है तथा निजी क्षेत्र में भी पूंजीगत निवेश बढ़ता है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के चक्र को बढ़ावा मिलता है जो अंतत: देश के कर संग्रहण में भी वृद्धि करने में सहायक होता है। मध्यवर्गीय परिवार के आय कर में कमी करने से बहुत सम्भव है कि भारत में औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले। क्योंकि कई देशों में यह सिद्ध हो चुका है कि कर की राशि को कम रखने से औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है इससे कर की दर को कम करने के उपरांत भी कर संग्रहण में वृद्धि होते हुए देखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में अभी भी अनऔपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था के करीब करीब बराबरी पर ही चलती हुए दिखाई देती है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक व्यवहारों के भारी मात्रा में डिजिटलीकरण करने के उपरांत भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में बहुत मदद मिली है और इसी के चलते ही वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रतिमाह के स्तर पर पहुंच सका है। अत: कुल मिलाकर देश में मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या जितनी तेज गति से आगे बढ़ेगी देश का आर्थिक विकास भी उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।

दरअसल, देश में कर संग्रहण में आकर्षक वृद्धि के बाद ही गरीब वर्ग की सहायता के लिए भी विभिन्न योजनाएं सफलता पूर्वक चलाई जा सकेंगी। अत: वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है कि मध्यवर्गीय परिवार गरीब परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने में सदैव आगे रहा है।

फ्रांस का धुर दक्षिणपंथ की ओर बढ़ता झुकाव

शोभना जैन

फ्रांस में संसदीय चुनाव के पहले चरण के बाद देश की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की पहली बार भारी विजय से इस पार्टी में नई उम्मीदें जगी हैं। हो सकता है कि पार्टी की इस विजय से फ्रांस में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार उसकी सरकार बने या यह भी हो सकता है कि किसी भी दल को चुनाव में बहुमत न मिल पाए और स्थिति त्रिशंकु सरकार की बने। चुनाव का दूसरा चरण अब सात जुलाई को है, जिससे मतदाता सरकार को लेकर निर्णायक फैसला कर सकेंगे। बहरहाल, वहां सरकार की घरेलू नीतियों की वजह से उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे फ्रांस में सरकार के गठन को लेकर जितनी उत्सुकता फ्रांसवासियों को है, वहीं खास तौर पर यूरोप में धुर दक्षिणपंथी पार्टी की इस विजय के यूरोप में पड़ने वाले असर को लेकर यूरोप भी उत्सुकता भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि यूरोप की राजनीति में

दक्षिणपंथ केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, इसकी पहुंच धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसी कशमकश में मैक्रों ने देश में मध्यावधि चुनाव कराने का बड़ा रिस्क लिया लेकिन पहले चरण के परिणाम उनके आकलन के अनुरूप नहीं निकले। दो हफ्ते पहले गत जून में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अचानक संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने का ऐलान कर दिया था। हालांकि वहां धीरे-धीरे दक्षिणपंथी पार्टी अपनी पकड़ धीरे-धीरे मजबूत कर रही थी, इसके बावजूद राष्ट्रपति मैक्रो ने संसदीय चुनावों का ऐलान किया। अहम बात यह है कि इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन जैसे यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों में भी दक्षिणपंथी दलों का वोट प्रतिशत बढ़ा है। चुनाव के पहले चरण में नेशनल रैली को 33.1 फीसदी वोट मिले हैं जबकि वामपंथी गठबंधन 28 फीसदी मत पाकर दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मैक्रों की पार्टी 20.7 फीसदी वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही है। पहले दौर की बढ़त के बाद धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन की आप्रवास विरोधी पार्टी नेशनल रैली के समर्थकों के हौसले बुलंद हैं। मरीन ली पेन और जॉर्डन बरदेला को फ्रांस की 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत के लिए 289 सीटों की जरूरत है। पहले चरण की विजय के बाद मरीन ली पेन ने हालांकि कहा कि मैक्रों ग्रुप का लगभग सफाया हो गया है लेकिन माना जा रहा है कि वो पूर्ण बहुमत से दूर रह सकती है। माना जा रहा है कि अगर दूसरे चरण में दक्षिणपंथी पार्टी या वामपंथी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो मैक्रों के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि मैक्रों को बहुमत वाली उस पार्टी के नेता को अपना प्रधानमंत्री चुनना होगा, जाहिर है कि ऐसी स्थिति में मैक्रों की योजनाओं को लागू करने में खासी परेशानी होगी।

क्या नए कानूनों से केस जल्दी निपटेंगे

सुधांशु रंजन

अपराध न्याय व्यवस्था में बीती एक जुलाई से व्यापक परिवर्तन आए हैं। औपनिवेशिक काल के तीन महत्वपूर्ण कानून नए देसी कानूनों द्वारा बदले गए हैं। भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) बनाए गए हैं। अब सारी प्राथमिकियां बीएनएस के तहत दर्ज की जाएंगी और नए कानूनों के तहत उनका ट्रायल होगा।

आईपीसी की 511 धाराओं के बरक्स बीएनएस में 358 धाराएं हैं। 21 नए अपराधों को इसमें शामिल किया गया है। 41 अपराधों में कारावास की अवधि, जबकि 82 में जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है। इसके अलावा 25 अपराधों में न्यूनतम दण्ड और छह अपराधों में दण्ड की जगह सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सामुदायिक सेवा कैसी होगी। जहां तक सीआरपीसी की बात है तो उसमें 484 धाराएं थीं, जबकि बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं। इसमें 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 14 पुरानी धाराओं को खत्म किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट की 166 धाराओं की जगह बीएसए में 170 धाराएं हैं।

नई व्यवस्था में प्राथमिकी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। प्राथमिकी की प्रति पीड़ित को मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। गिरफ्तारी का विस्तृत विवरण थाने और जिला मुख्यालय में ठीक से प्रदर्शित किया जाएगा। इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि दो महीने के अंदर इसे पूरा किया जा सके। पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर मामले में हुई प्रगति जानने का हक होगा।

नए कानूनों का पॉजिटिव पक्ष है निष्पादन की गति को तेज करना। इसके लिए टेक्नॉलजी पर काफी जोर है। डिजिटल साक्ष्य का प्रावधान है और फॉरेंसिक अन्वेषण को अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था की

सबसे बड़ी खामी यही मानी जाती है कि यहां मामले कई दशक चलते हैं। इसलिए स्थगन को भी दो तक सीमित किया गया है।

ध्यान रहे, स्थगन सीमित करने के प्रयास पहले भी हुए हैं। हुसैनारा खातून मामले (1978) में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार में तेज गति से ट्रायल होना भी शामिल है। बाद में कदरा पहाड़िया बनाम बिहार (1981) में अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी का तेज गति से ट्रायल नहीं होता है तो उसे अपने अधिकार को लागू कराने के लिए शीर्ष अदालत आने का अधिकार होगा। इसे अन्य कई मामलों में अदालत ने दोहराया परंतु महाराष्ट्र बनाम चम्पालाल पुंजाजी शाह (1981) में इस व्यवस्था को कमजोर कर दिया। उसने निर्णय दिया कि यद्यपि तेजी से ट्रायल अनुच्छेद 21 के द्वारा दिए गए फेयर ट्रायल का एक परोक्ष पहलू है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि देर से होने वाला ट्रायल अन्यायपूर्ण है।

संसद ने 1999 में सीपीसी में कई अहम संशोधन किए। इनमें एक यह था कि अदालत सुनवाई के दौरान तीन से अधिक स्थगन नहीं दे सकती है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने सेलम बार असोसिएशन (2005) में इन संशोधनों को एक तरह से निरस्त कर दिया। उसने निर्णय दिया कि समय-सीमा अदालत की अंदरूनी शक्तियों को कम नहीं कर सकती है, जो न्याय करने के लिए जरूरी है। ऐसे में देखना होगा कि दो संशोधन की सीमा बांधने वाले मौजूदा प्रावधानों पर अदालत का रुख कैसा होता है।

नए कानूनों के कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध भी है। कहा जा रहा है कि इनमें पुलिस को व्यापक अधिकार मिल गए हैं। बीएनएसएस की धारा 173 (3) के तहत जिन अपराधों में सजा तीन साल से ज्यादा और सात साल से कम है, उनमें पुलिस अधिकारी को 14 दिनों की छूट दी गई है एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने के लिए। यह शीर्ष अदालत द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश (2013) में दी गई व्यवस्था के विपरीत है कि शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। बाद के भी अनेक फैसलों में न्यायालय ने इसे दोहराया।

बीएनएस की धारा 113 में आतंकवादी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए अवैध गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) पहले से है। इससे पुलिस को बहुत ताकत मिल जाएगी। भारत में पुलिस सुधार की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। ध्यान रहे, कानून में बदलाव होने पर अदालत के हाथ भी बंध जाते हैं। मसलन, जब तक गांजा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आता था, न्यायालय आधा किलो गांजा बरामद होने पर भी जमानत दे देती थी। लेकिन बाद में उसे एनडीपीएस एक्ट के अंदर कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 20 ग्राम गांजा बरामद होने पर भी अदालत जमानत नहीं देती है।

अभी कई वर्षों तक पुलिस और अदालत को पुराने और नए, दोनों कानूनों के तहत काम करना होगा। इसलिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस सुधार पर भी काम करने की जरूरत है।

हाथ मिलाने की परंपरा देश के राजनीतिक विकास की प्रतीक

कल्याणी शंकर

यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में एक-दूसरे से हाथ मिलाया। यह पिछले सप्ताह स्पीकर ओम बिरला के चुनाव के बाद हुआ था। हाथ मिलाने की परंपरा देश के राजनीतिक विकास का प्रतीक है

यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में एक-दूसरे से हाथ मिलाया। यह पिछले सप्ताह स्पीकर ओम बिरला के चुनाव के बाद हुआ था। हाथ मिलाने की परंपरा देश के राजनीतिक विकास का प्रतीक है। यह परंपरा एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है। यह संसद के शुरूआती दिनों से चली आ रही है। उनके वैचारिक मतभेदों के बावजूद, यह सत्ता पक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच अपेक्षित सहयोग को प्रदर्शित करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने विपक्ष के नेता के रूप में राहुल की औपचारिक मान्यता को दर्शाया।

कांग्रेस पार्टी के भीतर नई गतिशीलता होगी और अपनी नई भूमिका में राहुल के लिए चुनौतियां होंगी। मोदी के शासन के 10 साल बाद, लोकसभा में विपक्ष का नेता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व फिर से संभाल लिया है और मोदी की भाजपा के खिलाफ शीर्ष राजनीतिक दावेदार के रूप में खड़े हैं। यह पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसमें कायाकल्प की उच्च उम्मीदें हैं। वह एक एकीकृत विपक्ष का निर्माण कर रहे थे, जो मोदी की भाजपा के लिए अधिक मजबूत चुनौती पेश कर सकता है। एक अनिच्छुक नेता से एक विपक्ष के नेता के रूप में राहुल का परिवर्तन उनके राजनीतिक विकास को दर्शाता है। 2 महीने की भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू करने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, जिसके कारण कांग्रेस ने 2024 में 2019 में जीती गई सीटों से दोगुनी सीटें हासिल कीं। इसका उद्देश्य लोगों से जुड़ना था। इसके बाद उन्होंने एक और यात्रा की। राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा, जो 2004 में अमेठी से सांसद बनने के साथ शुरू हुई, उनके लचीलेपन का प्रमाण है।

पिछले 2 दशकों में, उन्होंने कई चुनौतियों, आलोचनाओं और छूटे हुए अवसरों का सामना किया है।

उन्होंने कुछ वर्षों तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उनकी राजनीतिक यात्रा उनके नेतृत्व गुणों के बारे में संदेह और आलोचना से भरी रही। हालांकि, वे मजबूत और दृढ़ बने रहे और पी.एम. मोदी के विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी बन गए। महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद, राहुल महत्वपूर्ण समय पर गायब हो जाते हैं। उन्होंने यू.पी.ए. के 10 वर्षों के दौरान कैबिनेट मंत्री के रूप में काम नहीं करने का फैसला किया, इसके बजाय पार्टी पर ध्यान केंद्रित किया। उपहास के बावजूद, वे अपने पिता राजीव गांधी और अपनी मां सोनिया गांधी के नक्शेकदम पर चलते हुए आज विपक्ष के नेता बन गए। 18वीं लोकसभा के संक्षिप्त उद्घाटन सत्र के दौरान, राहुल ने एक विश्वसनीय विपक्षी नेता के रूप में काम किया। उन्होंने मणिपुर की स्थिति, अग्निपथ योजना, नीट परीक्षा और संविधान सहित कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर आक्रामक हमला किया।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की अधिक महत्वपूर्ण उपस्थिति है। 543 सदस्यों वाले सदन में एन.डी.ए. के 292 सदस्यों की तुलना में विभिन्न विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' ब्लॉक में 234 सदस्य और तीन स्वतंत्र सांसदों का समर्थन है। अपर्याप्त संख्या के कारण कांग्रेस विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं कर सकी। राहुल के कई हमलों ने भाजपा को भी झकझोर दिया, जब उन्होंने कहा कि भाजपा के कई लोग ड्क्षहदू नहीं हैं, तो भाजपा ने भी पलटवार किया। उनके उद्घाटन भाषण ने दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा टकराव शुरू कर दिया। पहले सत्र के अंत में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी-जो अब विपक्ष के नेता हैं-को 'बालक बुद्धि' के रूप में वर्णित किया, जिसका अर्थ है कि वह एक बच्चे की तरह दिमाग वाले वयस्क व्यक्ति हैं।

मोदी द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल राहुल की नेतृत्व शैली के लिए एक अपमानजनक संदर्भ था, जिसका अर्थ है कि वह अपरिपक्व हैं और उनमें एक राजनीतिक नेता के रूप में अपेक्षित बुद्धि का अभाव है। पी.एम. मोदी ने कहा कि ''इस व्यक्ति ने मुझे मारा, उस व्यक्ति ने मुझे मारा, मुझे यहां मारा गया, मुझे वहां मारा गया... यह नाटक सहानुभूति हासिल करने के लिए खेला जा रहा है।'' विपक्ष के नेता के रूप में, राहुल गांधी के पास अब नई जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उन्हें विपक्षी दलों को एकजुट करने, महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने, विपक्ष को एकजुट रखने और अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम सौंपा गया है। उनकी भूमिका के लिए उन्हें संसदीय नियमों और विनियमों में निपुणता हासिल करनी होगी और विपक्ष का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यावहारिक संचार कौशल विकसित करना होगा। इन जिम्मेदारियों का भार महत्वपूर्ण है और यह भारतीय राजनीति के भविष्य को आकार देगा।

वह लोक लेखा समिति के प्रमुख भी बन सकते हैं, यह पद आमतौर पर संसद में विपक्ष को दिया जाता है। इससे उन्हें अन्य संसदीय समितियों के लिए सदस्यों का चयन करने और भारत के कुछ सबसे प्रभावशाली सिविल सेवकों को चुनने में भाग लेने का अवसर मिलेगा। विपक्ष के नेता के रूप में, राहुल ने मोदी और नए अध्यक्ष ओम बिरला को चुनौती दी। उन्होंने अध्यक्ष से कहा, ''असली सवाल यह नहीं है कि सदन कितनी अच्छी तरह चल रहा है, बल्कि यह है कि क्या यह चल रहा है और लोगों की आवाज कितनी सुनी जा रही है।''सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच चल रही लड़ाई संसदीय सत्रों से परे भी जारी रहने की उम्मीद है। यह लड़ाई संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह होगी। राहुल संसद में पहले पन्ने पर ध्यान खींचने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने अच्छी शुरूआत की है।

ऐतिहासिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा ब्रिटेन

केएस तोमर

लेबर पार्टी और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही है। 1900 में स्थापित लेबर पार्टी ने अक्सर ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष समेत उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखाई है। रामसे मैकडोनाल्ड जैसे लेबर नेता ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मुखर आलोचक थे। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे भारतीय नेताओं के साथ संबंधों को बढ़ावा देने में लेबर पार्टी के समर्थन की अहम भूमिका थी। क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ब्रिटेन के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध बने। लेबर पार्टी का रुख भी भारत के प्रति सकारात्मक है। कीर स्टार्मर ने चुनाव अभियान के दौरान लगातार ब्रिटेन-भारत संबंधों को बढ़ावा देने, आर्थिक साझेदारी मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग पर जोर देने की प्रतिबद्धता जताई है। चौदह वर्षों के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी के लिए नए युग की शुरुआत हुई है, जिसने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। लेकिन नई सरकार के समक्ष कठिन चुनौतियां भी हैं, जिनका उसे सामना करना पड़ेगा। ब्रेग्जिट के बाद की वास्तविकताओं से निपटने और कमजोर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने से लेकर भारत और अमेरिका के साथ नाजुक संबंधों को संभालने तक, लेबर पार्टी की सरकार को कई मोर्चों पर जूझना पड़ सकता है। लेबर पार्टी के कई उम्मीदवारों की जीत में अनिवासी भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनाव में ब्रिटेन स्थित 15 लाख अनिवासी भारतीयों की भूमिका उनकी पर्याप्त उपस्थिति एवं समुदाय में सक्रिय भागीदारी के कारण महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश भारतीयों के साथ अनिवासी भारतीय वहां एक प्रभावशाली मतदाता समूह हैं, जो अक्सर ऐसे मुद्दों पर लामबंद होते हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। कीर स्टार्मर और लेबर पार्टी के प्रति समर्थन के संबंध में, विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय मूल के मतदाताओं में लेबर पार्टी के प्रति झुकाव का कारण पार्टी का भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए उसकी पक्षधरता है। निश्चित रूप से कुछ अनिवासी भारतीयों ने अपनी प्राथमिकताओं एवं दृष्टिकोण के आधार पर कंजर्वेटिव एवं अन्य पार्टियों का भी समर्थन किया होगा। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के अलावा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच इससे संबंधित वार्ता में पहले ही जबर्दस्त प्रगति हो चुकी है। अब जबकि भारत और ब्रिटेन में मैत्रीपूर्ण सरकारें सत्ता में आ चुकी हैं, इसलिए एफटीए को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में जटिलताएं भी हैं। मसलन, वीजा विनियमन, व्यापार अवरोधों और भू-राजनीतिक गतिशीलता जैसे मुद्दों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए। नई सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने और दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली साझेदारी के लिए सक्रिय कूटनीति की आवश्यकता होगी। लेबर पार्टी को विरासत में संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था मिली है। आर्थिक विकास ठहर गया है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है और सार्वजनिक ऋण अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। नई सरकार के सामने ऐसी नीतियों को बनाने और लागू करने की चुनौती है, जो राजकोषीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए विकास को बढ़ावा दे। ब्रिटेन की नई सरकार को घरेलू और विदेशी, दोनों ही स्तरों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और ब्रेग्जिट के बाद के परिदृश्य को संभालने से लेकर अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने और घरेलू चिंताओं को दूर करने तक, आगे का कार्य बहुत बड़ा है। हालांकि, स्पष्ट दृष्टिकोण, व्यावहारिक नीतियों और सामाजिक न्याय और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ लेबर सरकार के पास ब्रिटेन के लिए प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने का अवसर है।

हिंदू धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व

हिंदू धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जिस प्रकार संस्कृत भाषा को देववाणी कहा जाता है, उसी प्रकार गंगाजी को देव नदी कहा जाता है। गंगा भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की परम पवित्र नदी है। इस तथ्य को भारतीय तो मानते ही है, विदेशी विद्वान भी इसे स्वीकार करते है।

प्रचलित मान्यता

ऐसा माना जाता है कि गंगा जी स्वर्गलोक से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को पृथ्वी पर उतरी थीं। इसी दिन सूर्यवंशी राजा भगीरथ की पीढ़ियों का परिश्रम और तप सफल हुआ था। उनके घोर तप के फलस्वरूप गंगाजी ने शुष्क तथा उजाड़ प्रदेश को उर्वर तथा शस्य श्यामल बनाया और भय-ताप से दग्ध जगत के संताप को मिटाया। उसी मंगलमय सफलता की पुण्य स्मृति में गंगा पूजन की परंपरा प्रचलित है।

भारतीय संस्कृति और गंगा

गंगा, गीता और गौ को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व दिया गया है। प्रत्येक आस्तिक भारतीय गंगा को अपनी माता समझता है। गंगा में स्नान का अवसर पाकर कृत-कृत्य हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा के प्रति अपनी सारी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान और पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते है। गंगा दशहरा के दिन यदि संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए अथवा किसी अन्य नदी, जलाशय में या घर के ही शुद्ध जल से स्नान करें, पर गंगा जी का स्मरण और पूजन करे।

गंगा पूजन के साथ उनको भूतल पर लाने वाले राजा भागीरथ और उद्गम स्थान हिमालय का भी पूजन नाम मंत्र से करना चाहिए। इस दिन गंगा जी को अपनी जटाओं में समेटने वाले भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो इस दिन दस फूलों और तिल आदि का दान भी करना चाहिए।

पौराणिक कथा

प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञीय अश्व की रक्षा के लिए उनके साठ हजार पुत्र उसके पीछे-पीछे चले। इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ के अश्व को पकड़वा कर कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया। सागर पुत्र जब अश्व को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में गए, तो वहां यज्ञ के घोड़े को देखकर ऋषि को भला-बुरा कहा। ऋषि को इंद्र के षड्यंत्र का पता न था अतएव उन्हे भी क्रोध आया और उन्होंने हुंकार से राजकुमारों को भस्म कर दिया।

जब बहुत दिन बीत गए और कोई भी राजकुमार लौट कर नहीं आया तो राजा सगर ने अपने नवयुवक पौत्र अंशुमान को उनका पता लगाने के लिए भेजा। उसने घोड़े का पता लगाया और अपने पूर्वजों की दुर्दशा भी देखी। उसे गरुड़ द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि भस्म हुए राजकुमारों का उद्धार तभी हो सकता है, जब स्वर्गलोक से गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जाए और इन सबकी भस्मी का स्पर्श गंगाजल से कराया जाए। अंशुमान ने वैसा ही किया। इसके बाद इसी वंश में आगे चल कर राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ परम प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा हुए। वह गंगा जी को लाने केलिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तप करने लगे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से देवताओं को भी विचलित कर दिया। देवों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे भगीरथ को संतुष्ट करे। इसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं के साथ राजा के पास गए और उनसे अभीष्ट वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगावरतण की प्रार्थना की। ब्रह्माजी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु यह भी कहा कि गंगा जी की वेगवती धारा को भूतल पर संभालने का प्रबंध तु6हे करना पड़ेगा। इसके लिए राजा ने घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया और उन्होंने गंगा की वेगवती धारा को संभालने का कार्य अंगीकार कर लिया। उसके बाद शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को रोका और बाद में अपनी जटा को निचोड़ कर बिंदु के रूप में गंगा जी को बाहर निकाला। वह बिंदु शिवजी के निवास स्थान कैलास पर्वत के पास बिंदु सरोवर में गिरा। वहां पर तत्काल गंगाजी सात धाराएं हो गई और वे अलग-अलग दिशाओं में फैल गई।

अथक भागीरथ प्रयत्न

गंगा जी की कृपा से भारत का मानचित्र ही बदल गया है। गंगावतरण के प्रमुख साधक भगीरथ की साधना, तप और अति विकट परिश्रम ने यह अमृत फल प्रदान किया है। उनके इस कठिन प्रयत्न की वजह से ही भगीरथ प्रयत्न एक मुहावरा बन गया है और गंगा जी का एक नाम भागीरथी पड़ गया। गंगावतरण की तिथि गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी में गंगा स्नान, गंगा पूजन और दान का विशेष महत्व है।

सच्ची आध्यात्मिकता

एक व्यक्ति किसी फकीर के पास साधना सीखने गया। फकीर की चारों ओर बहुत ख्याति थी। उनके आशीर्वाद से बीमार स्वस्थ हो जाते थे और लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थीं। दूर-दूर से पीड़ित लोग उनके यहां आते, दुआएं मांगते और प्रसन्न होकर जाते। जब वह आदमी संत के पास पहुंचा तो देखा कि फकीर एक टोकरी में से दाना निकालकर पक्षियों को चुगा रहे थे। उन्हें चुगते देख कर वे बच्चों की तरह खुश हो उठते थे। इस तरह लंबा समय बीत गया। न फकीर ने उस व्यक्ति की ओर देखा और न दाना चुगाना ही बंद किया। आने वाला परेशान हो गया। वह फकीर की ओर बढ़ा। उसे सामने देखते ही फकीर ने टोकरी उसके हाथों में थमा दी और कहा, अब तुम पक्षियों के साथ आनंद का अनुभव करो। वह व्यक्ति सोचने लगा, कहां तो मैं इनसे आध्यात्मिक साधना का रहस्य जानने आया हूं और ये हैं कि मुझे पक्षियों को दाना चुगाने को कह रहे हैं। फकीर ने उसके मन की बात पढ़ ली। वह बोले, स्वयं की परेशानियों को भूल कर दूसरों को आनंद पहुंचाने का प्रयत्न ही जीवन की हर सिद्धि और आनंद का राज है। यदि तुम स्वयं सुख और आनंद पाना चाहते हो, तो वही दूसरे को भी देना सीखो। तुम यदि यह साध सकोगे तो तुम्हारी सारी साधना हो जाएगी। जो लोग आध्यात्मिकता को किसी खास नियम और जीवनशैली में देखते हैं, वे उसके नैसर्गिक पक्ष से वंचित रह जाते हैं। खरा आध्यात्मिक जीवन दूसरों को सुख बांटने में होता है। उसमें आनंद और खुलेपन का अनुभव होता है। एक छोटे से उदाहरण से वह व्यक्ति आध्यात्मिकता के रहस्य को समझ गया।

अहंकार है पतन का जनक

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं नैमा विद्युतो भान्ति कुतो-यम्-अग्निः
तमेव भान्तम्-अनुभाति सर्वंतस्य भासा सर्वम्-इदम् विभाति

अर्थ : वास्तव में सूर्य, चन्द्र, विद्युत आदि में जो प्रकाश है, वह सूर्य, चन्द्र और विद्युत की सत्ता में नहीं है- इन सबका प्रकाशक सर्वाधिष्ठान शुद्ध-चैतन्य ब्रह्म ही है।

कठोपनिषद् में एक सुन्दर आख्यान आता है।

एक समय देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई तो उन्हें अहंभाव हो गया। विजय का श्रेय लेने के लिए अग्नि, वायु आदि सभी देवता अपने-अपने पराक्रम का यशोगान करने लगे। देवताओं का इस प्रकार अहंकार बढ़ा हुआ देखकर सर्वनियन्ता परमात्मा ने सोचा कि अहंकार तो पतन का हेतु होता है, इसलिए देवताओं को पतन से बचाने के लिए इनका अहंकार चूर कर देना आवश्यक है। जहां देवगण मिलकर अपनी-अपनी विभूति गाथा गा रहे थे, वहीं आकाश में एक विचित्र आकृति वाला यक्ष उत्पन्न हो गया। देवताओं की दृष्टि उस पर गई तो वे निश्चय नहीं कर सके कि यह क्या है। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई दैत्य तो नहीं है।

- उसका पता लगाने के लिए सबने अग्निदेव से कहा कि आप बड़े ही पराक्रमशाली हैं, आप ही जाकर पता लगाइए कि यह कौन है और यहां इसके आने का क्या कारण है। अग्निदेव यक्ष के निकट गये।
- यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? अग्नि ने बड़े गर्व से कहा - मैं अग्नि हूं और 'जातवेदा' नाम से जगत् में विख्यात हूं। इस प्रकार गर्वीला उत्तर सुनकर यक्ष ने एक तिनका अग्नि के समाने रख दिया और कहा कि इसे जला दो।
- अग्नि ने बार-बार प्रयत्न किया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वह तृण जला नहीं। अग्नि लज्जित होकर वापिस लौट आई, तब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ।
- सब ने मिलकर वायु को प्रेरित किया। कहा कि आप भी बड़े प्रभावशाली हैं, आप इसका पता अवश्य ही लगा लेंगे। वायुदेव यक्ष के निकट पहुंचे। यक्ष ने पूछा- तुम कौन है? वायु ने कहा है- हम वायुदेव हैं। यक्ष ने पूछा-तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? वायु ने उत्तर दिया- मैं क्षणभर में समस्त भूमण्डल को यहां का वहां कर सकता हूं, चाहे जिसे चाहे जहां उड़ाकर फेंक सकता हूं। यक्ष ने वही तिनका वायु के सामने रख दिया और कहा- इसे उड़ा ले जाओ। वायु ने सरलता से उड़ाना चाहा, तिनका हिला तक नहीं, वायु ने अपना पूरा बल लगाया, पर तिनका उस स्थान से टसमस भी नहीं हुआ। वायु शिथिल होकर लौट आई।

सब देवता बड़े विस्मय और भय में पड़ गये। सब ने मिलकर इन्द्र से कहा- आप देवराज हैं। आप हम सब में बुद्धिमान हैं। यह कोई भयंकर आपति हम लोगों पर आ रही है; कृपा करके युक्तिपूर्वक ढंग से पता लगवाइए कि यह क्या है। इन्द्र अपना पराक्रम बटोरकर यक्ष के समीप पहुंचे। यक्ष ने इनकी इतनी अवहेलना की कि वह इनसे बोला तक नहीं। और वहीं अन्तर्ध्यान हो गया। तब इन्द्र का अभिमान जाता रहा। उसने विनम्र होकर भगवती का ध्यान किया और प्रार्थना की। तब विद्यादेवी ने उमा के रूप में प्रकट होकर इन्द्र को समझाते हुए कहा-'यह यक्ष जो तुम लोगों के सामने प्रकट हुआ था, वह सर्वनियन्ता परब्रह्म परमात्मा ही था; उसी की सत्ता से समस्त जगत सत्तावान् है; उसी की शक्ति से अग्नि, वायु आदि देवगण शक्तिमान होते हैं; उसी के प्रकाश से सूर्य,चन्द्र में प्रकाश है, उसी की शक्ति से ही आप लोग शक्तिमान् हैं ; यह जो आप लोगों की विजय हुई है, वह उसी की विजय है। आप लोगों को अनावश्यक अहंकार हो गया था, इसी हेतु से आपका दर्पदलन करने के हेतु वह यक्ष के रूप में प्रकट हुआ था। आप लोगों को चाहिए कि जिसकी इच्छा के विरुद्ध एक तृण भी नहीं हिल सकता, जो सूर्य, चन्द्र आदि सबको अपने प्रकाश से प्रकाशित कराता है, उसी सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश परब्रह्म परमात्मा की ही प्रधानता मानें, व्यर्थ का अहंभाव अपने मन में न आने दें।'

अक्खड़, निडर और संत कवि कबीरदास

कबीर समाज में फैले आडम्बरों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने सबको एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। वह लेखक और कवि थे। उनके दोहे इंसान को जीवन की नई प्रेरणा देते हैं। कबीर ने जिस भाषा में लिखा, वह लोक प्रचलित तथा सरल थी। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, इसके बावजूद वे दिव्य प्रतिभा के धनी थे।

संत कबीरदास जी का जन्म संवत् 1455 की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। काशी के इस अक्खड़, निडर एवं संत कवि का जुलाहा परिवार में पालन पोषण हुआ। उनके जीवन के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं जिनमें एक के अनुसार वह जगद्गुरु रामानन्द स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे लेकिन ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आयी। उसे नीरु नाम का जुलाहा अपने घर ले आया। उसी ने उसका पालन-पोषण किया। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में प्रकट हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानन्द के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुईं। कबीर संत रामानंद के शिष्य बने गये और समाज में अलख जगाने लगे। कबीर समाज में फैले आडम्बरों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने सबको एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। वह लेखक और कवि थे। उनके दोहे इंसान को जीवन की नई प्रेरणा देते हैं। कबीर ने जिस भाषा में लिखा, वह लोक प्रचलित तथा सरल थी। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, इसके बावजूद वे दिव्य प्रतिभा के धनी थे। कबीरदास जी को हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सम्प्रदायों में बराबर का सम्मान प्राप्त था। दोनों सम्प्रदाय के लोग उनके अनुयायी थे। यही कारण था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। हिन्दू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिन्दू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। किन्तु छीना झपटी में जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा जिसे सभी धर्मों में समानता प्राप्त है। यह कबीर जी की ओर से दिया गया संदेश था कि इंसान को फूलों की तरह होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक जैसा भाव होना चाहिए। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिये और आधे मुस्लिमों ने और अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार किया। काशी के बारे में कहा जाता है कि जो यहां मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन कबीर इस बात को नहीं मानते थे। अपने अंतिम समय वह काशी छोड़ मगहर चले गये और वहीं देह त्याग किया। मगहर में ही कबीर की समाधि है जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग पूजते हैं।कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। वह एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोज़ा, ईद, मसजिद, मंदिर आदि को वह नहीं मानते थे। कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते थे क्योंकि यही लोग मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। कबीर की कवि ताओं का एक-एक शब्द पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग व स्वार्थपूर्ति पर वार करता है। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने जो मुंह से बोला उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीर के समस्त विचारों में राम-नाम की महिमा ही प्रतिध्वनित होती है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं- रमैनी, सबद और साखी। इनके नाम पर कबीरपंथ नामक संप्रदाय भी प्रचलित है। कबीरपंथी इन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं और इनके संबंध में बहुत सी चमत्कारपूर्ण कथाएं भी सुनी और सुनाई जाती हैं। कबीर का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। कहा जाता है कि कबीर की कमाल और कमाली नाम की दो संतानें थीं। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विदित होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। कमाली का उल्लेख उनकी बानियों में कहीं नहीं मिलता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

संदेशखाली पर ममता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि राज्य को किसी की रक्षा करने में दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? सुनवाई की आखिरी तारीख पर, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, धन्यवाद। शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 29 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि राज्य को कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल में हुआ विस्तार

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में आए वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत को सोमवार को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। करीब दो महीने पहले कांग्रेस छोड़ने वाले रावत को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा उनकी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। गत 30 अप्रैल को कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले रावत चंबल क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली नेताओं में शुमार हैं। पहली बार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाले रावत प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और वह श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से छठवीं बार विधायक चुने गए हैं। रावत ने शपथ ग्रहण के ठीक पहले विधायक पद से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद विजयपुर में अब दोबारा चुनाव होंगे।

विधानसभा में हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास प्रस्ताव

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने 4 जुलाई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ने सोमवार को 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। नए मुख्यमंत्री को 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। झारखंड विधानसभा की वर्तमान ताकत 76 है। सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने राज्यपाल को 44 विधायकों की समर्थन सूची सौंपी थी जब 3 जुलाई को हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। जेएमएम, कांग्रेस और राजद विधायकों ने फ्लोर टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने का भरोसा जताया था, लेकिन बीजेपी का तर्क था कि यह आसान नहीं होगा। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन को 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था। 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से कुछ समय पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।

केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ प्रशासन से मांगा जवाब

नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। उन्होंने न्यायिक हिरासत अवधि के दौरान वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकें करने के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। फिलहाल, इस मामले पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री के आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसमें दावा किया गया था कि वह पूरे देश में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं। निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार का दावा करते हुए मामलों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठक की आवश्यकता है।

मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है। उन्होंने शराब नीति मामले में ट्रायल के शुरू होने में देरी की शिकायत की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले में ट्रायल देरी से शुरू किया गया। सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने का आश्वासन दिया। बता दें, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ईडी ने नौ मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। कोरोना काल के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी।

राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से मिलकर भारत-रूस संबंधों पर चर्चा के लिए उत्सुक

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के साथ ही एक शांतिपूर्ण एवं स्थिर क्षेत्र के लिए सहायक भूमिका निभाने को उत्सुक हैं। रूस और ऑस्ट्रिया के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में यह बात कही। मोदी और पुतिन मंगलवार को 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। इस दौरान वे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के तरीके तलाशने पर विमर्श करेंगे।

रूस में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होंगे। यह, विगत 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की पहली यात्रा होगी। मोदी ने बयान में कहा, भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में और बढ़ी है, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों से लोगों का संपर्क आदि क्षेत्र शामिल हैं।'' उन्होंने कहा, मैं, मेरे मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय एवं

वैश्विक मामलों पर दृष्टिकोण साझा करने को लेकर आशान्वित हूं।'' उन्होंने कहा, ''हम शांतिपूर्ण एवं स्थिर क्षेत्र के लिए सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। यह यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी।'' प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया को भारत का 'दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार' बताया और कहा कि इस दौरे पर उन्हें राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वान डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, ''ऑस्ट्रिया हमारा दृढ़ और विश्वसनीय भागीदार है और हम लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं।''

उन्होंने कहा, पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। मैं नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी चर्चाओं को लेकर आशान्वित हूं।'' मोदी ने कहा कि वह दोनों पक्षों की कारोबारी हस्तियों के साथ विचारों के आदान-प्रदान को लेकर आशान्वित हैं ताकि परस्पर लाभकारी व्यापार एवं निवेश अवसरों की संभावना तलाशी जा सके। उन्होंने कहा, मैं ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करुंगा, जो अपने पेशेवर रूख और आचरण के लिए जाने जाते हैं।''

पीएम मोदी के लिए क्यों जरूरी है मॉस्को यात्रा? विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि रूस के साथ संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। एएनआई से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह एक पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए बैठकर रिश्ते पर चर्चा करने का बेहतरीन मौका। यह किसी भी रिश्ते का जायजा लेने का एक तरीका है। सबसे बड़े बदलावों में से एक यह है कि रूस के साथ हमारे आर्थिक संबंध काफी बढ़ गए हैं। नेतृत्व के स्तर पर, यह पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति के लिए एक बड़ा अवसर होगा। पुतिन को बैठें और सीधे एक-दूसरे से बात करें।

जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों की अलग-अलग व्यस्तताओं के कारण वार्षिक शिखर सम्मेलन में थोड़ी देरी हुई। हमारे वार्षिक शिखर सम्मेलन में थोड़ी देरी हुई, यह एक अच्छी परंपरा है, हम दो देश हैं जिनका साथ मिलकर काम करने का एक मजबूत इतिहास है। हमने वार्षिक शिखर सम्मेलन की आवश्यकता को महत्व दिया। पिछले साल जब मैं मॉस्को गया था, तो मैं प्रधानमंत्री का संदेश लेकर गया था कि हम वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसे देर-सवेर जल्द ही करेंगे। यह एक नियमित पुनरावृत्ति है। यह किसी भी रिश्ते का जायजा लेने का एक तरीका है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों का साथ मिलकर काम करने का एक स्थिर इतिहास है। हम दुनिया भर में हो रही घटनाओं को देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम किसी स्थिति में कोई सुधार करना चाहते हैं, हम मिलते हैं और चर्चा करते हैं। यह बैठक कुछ ऐसी थी जिसके घटित होने का इंतजार किया जा रहा था। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान रूस-यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया था देश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा बिल्कुल...बहुत स्पष्ट और दृढ़ता से...कई भारतीयों

मोदी रूस दौरे पर रवाना, कांग्रेस का तंज

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा को लेकर उन पर कटाक्ष किया और कहा कि गैर-जैविक प्रधानमंत्री को अभी तक हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने के लिए कुछ घंटों का भी समय नहीं मिला है, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा एक साल से अधिक समय में उनकी तीसरी यात्रा होगी। राहुल गांधी सोमवार को असम के सिलचर पहुंचे। वह तीन अलग-अलग स्थानों पर राहत शिविरों का दौरा करने के लिए मणिपुर जाने से पहले फुलर्टल में एक राहत शिविर का दौरा करेंगे। जयराम रमेश मे अपने एक्स पोस्ट में कहा कि नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आज मास्को जा रहे हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता असम और मणिपुर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वालों ने इस बात को लेकर बड़े-बड़े दावे किए हैं कि उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को कुछ समय के लिए रुकवा दिया था। उनकी मॉस्को की इस यात्रा के दौरान संभवत और भी विचित्र दावे किए जाएं। रमेश ने कहा कि चौदह महीने पहले राज्य में भड़की हिंसा के बाद से यह राहुल गांधी की मणिपुर की तीसरी यात्रा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 3 मई 2023 को राज्य में गंभीर संकट उत्पन्न होने के बाद नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को कुछ घंटों के लिए भी मणिपुर जाने का समय नहीं मिला और न ही उन्होंने इसकी इच्छा जताई। उन्होंने न तो राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाक़ात की है, जो कि उनकी अपनी ही पार्टी के हैं।

मणिपुर में राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मिले राहुल गांधी

■ **कांग्रेस सांसद के दौरे से पहले जिरिबाम में गोलीबारी**

इंफाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी के दौरे से पहले जिरिबाम क्षेत्र में सोमवार की सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। सुबह के साढ़े तीन बजे अज्ञात लोगों ने इलाके में गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी मैतेई इलाके में की गई।

गोलीबारी की जानकारी पाकर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। सुबह के सात बजे तक सुरक्षाकर्मियों और बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी जारी रही। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया। बता दें कि मणिपुर में पिछले एक साल से जातीय हिंसा जारी है।

राहुल गांधी के राहत शिविर में लोगों से मुलाकात को लेकर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष देबब्रत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जिरिबाम में हाल ही में हुए हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए राहुल गांधी यहां आए। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में स्थिति सामान्य हो गई है। सब ने इसे मान लिया। लेकिन तथ्य यह है कि राहत शिविरों के पीड़ितों ने अपनी कहानियां सुनाईं। उन्होंने बताया कि उनका सबकुछ तबाह हो चुका है। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। राहुल गांधी ने पीड़ितों से उनकी कहानी सुनी।

राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। राज्य में पिछले साल जातीय हिंसा शुरू होने के बाद जून 2023 में वह मणिपुर आए थे और इस साल की शुरुआत में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी इसी राज्य से की थी।

मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पिछले साल तीन मई को पर्वतीय जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थीं।

राहुल के मणिपुर दौरे पर भाजपा का तंज

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे है। वह यहां राहत शिविरों का दौरा करेंगे और आज शाम मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हालांकि, इसको लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा ने दावा किया है कि संवेदनशील मामले पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है। वहां शांति लाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं...संसद में क्या हंगामा मचा?

भाजपा नेता ने आगे कहा कि नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब देने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। यह बेहद दुखद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मणिपुर के जिरिबाम जिले में एक राहत शिविर का दौरा किया। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि राहुल जिरिबाम उच्च माध्यमिक स्कूल में बनाए राहत शिविर में पहुंचे और उसमें रह रहे लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया, ''जिरिबाम राहत शिविर में राहुल ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत की।'' उन्होंने बताया कि इससे पहले, राहुल ने असम में एक राहत शिविर का दौरा किया और उसके बाद वह सड़क मार्ग से जिरिबाम पहुंचे।

खेल
प्रमुख समाचार

तीसरे टी20 में भारतीय टीम में होंगे 3 बड़े बदलाव

हरारे। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने धांसू अंदाज में जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली। पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर आगे जाने का प्रयास करेगी।

इस मैच में भारतीय टीम में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। टीम इंडिया में पिछले दो मैचों के दौरान कुल चार खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। अब कुछ पुराने नामों को टीम में वापस देखा जा सकता है। पिछले दो मैचों में जिन खिलाड़ियों को बाहर रखा गया था, उनको टीम में लाने का समय है।

यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल किये गए थे। दोनों को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पिछले दो टी20 मैचों में आराम दिया गया था।अब उनको टीम में शामिल करना तय माना जा रहा है। सैमसन और जायसवाल दोनों ही टीम के अहम खिलाड़ी हैं।

वर्ल्ड कप में फाइनल तक टीम इंडिया के साथ खेलने वाले शिवम दुबे को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। वह भी सलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। सैमसन, जायसवाल और शिवम दुबे की जगह अब तक टीम में हर्षित राणा, साई सुदर्शन और जितेश शर्मा को शामिल किया गया था। तीनों को टीम से बाहर रखा जाएगा। तीन बड़े नामों की एंट्री होने से इनका पत्ता कटना तय नजर आ रहा है। इससे प्लेइंग इलेवन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले मैच में जीत दर्ज करने के बाद भी टीम इंडिया में परिवर्तन होगा।

भारत की प्लेइंग 11 ऐसी हो सकती है

यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 36 अंक फिसला तो निफ्टी 24,321 पर बंद

नईदिल्ली। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स के नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन यानी सोमवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज गिरावट के साथ खुला और कारोबार के दौरान 80,067.46 अंक के ऊंचे तथा 79,731.83 अंक के निचले स्तर तक गया। अंत में सेंसेक्स 36.22 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,960.38 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाइटन का शेयर सबसे ज्यादा 3.54 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक के शेयर प्रमुख रूप से गिरावट में रहे। दूसरी तरफ, आईटीसी का शेयर आज 2.27 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ।

सेंसेक्स में रतन टाटा की टीसीएस कंपनी टॉप पर

नईदिल्ली। देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) बाजार मूल्यांकन के मामले में सेंसेक्स की 10 कंपनियों में टॉप पर है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सेंसेक्स की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से आठ के बाजार मूल्यांकन में पिछले सप्ताह 1,83,290.36 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। सबसे अधिक फायदे में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस रहीं। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 963.87 अंक या 1.21 प्रतिशत चढ़ गया। सेंसेक्स में 1 से 5 जुलाई के बीच कारोबारी सप्ताह में टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 38,894.44 करोड़ रुपये बढ़कर 14,51,739 ।53 करोड़ रुपये हो गया।

बजट में दिखेगा आर्थिक विकास का विजन, न कि प्रोत्साहन

नईदिल्ली। भारत में बजट का इंतजार करीब-करीब खत्म होने वाला है। महज दो सप्ताह में (23 जुलाई को) भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। इस बीच, ग्लोबल इंवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स का बयान जारी हुआ है। फर्म के एनालिस्ट्स ने हालिया नोट में कहा कि आने वाला बजट राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर चलने वाला होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मोदी 3.0 बजट मामूली प्रोत्साहन उपायों के बजाय व्यापक आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि सार्वजनिक कर्ज की अधिकता को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सीमित राजकोषीय धन है। इसके अलावा, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ने लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ग्रोथ को बढ़ावा दिया है, जिसे नीति निर्माता छोड़ना नहीं चाहेंगे।

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के सभी 5 स्टार होटल बिके

मुंबई। अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की शादी से पहले की रस्मों को लेकर मुंबई में होटलों की बुकिंग पर बड़ा असर डाला है। होटल की कीमतों पर भी बड़ा असर देखने को मिला है। ट्रैवल और होटल वेबसाइटों के अनुसार, मुंबई के प्रमुख रियल एस्टेट केंद्र बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में दो मुख्य होटल संपत्तियां बिक चुकी हैं। बीकेसी, मुंबई का एक प्रमुख रियल एस्टेट केंद्र है, जहां शादी समारोह होना है। एक होटल 14 जुलाई को 91,350 रुपए प्रति रात्रि की दर से कमरे की पेशकश कर रहा है, जबकि सामान्य किराया 13,000 रुपए प्रति रात्रि है। अंबानी परिवार के इस सदस्य की शादी 12 जुलाई को मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मेहमान कहां ठहरेंगे।

आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र को नयी सरकार से उम्मीदें

सतीश सिंह

नरेंद्र मोदी के 2014, 2019 और अब 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास के मोर्चे पर और बेहतरी आने की उम्मीदें हैं। क्योंकि 2014 और 2019 की अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सेवा आदि क्षेत्रों को विकसित करने एवं सुधार लाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। इस क्रम में सबसे कारगर और समीचीन कदम आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में उठाये गये हैं। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान भारत आर्थिक रूप से विश्व में एक मजबूत देश बनकर उभरा है। इसलिए, देशवासियों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत 2027 में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 2030 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 में विकसित देश बन सकता है।

वर्ष 1947 से ठीक 60 वर्षों के बाद भारत की जीडीपी 2007 में एक ट्रिलियन डॉलर की हुई और 2014 में दो ट्रिलियन डॉलर की हो गयी तथा 2019 में तीन ट्रिलियन डॉलर की। वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी थी, जबकि 2019 में यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी। वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से जीडीपी में वृद्धि दर्ज हुई और समग्र रूप से वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 8.2 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह सात प्रतिशत रही। 'द इंडियन इकोनॉमी- ए रिव्यू' रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत से अधिक रह सकती है। वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत रही थी, जबकि 2022 में 7.3

प्रतिशत। चूंकि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसलिए, 2024 से 2027 तक बेरोजगारी दर के आठ प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है। भारत में मुद्रास्फीति दर 2023 में 5.5 प्रतिशत रही है, जबकि 2022 में यह 6.7 प्रतिशत रही थी।

मई 2024 में खुदरा महंगाई 4.75 प्रतिशत रही, जो 12 महीने का निचला स्तर था। वर्ष 2024 से 2027 के दौरान इसके क्रमशः 4.6, 4.1, 4.1 और 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस आधार पर कहा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था आसानी से 2027 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की बन सकती है। 'द इंडियन इकोनॉमी- ए रिव्यू' रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा किये जा रहे आर्थिक सुधारों के चलते ही भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकी है। इस रिपोर्ट में यह संभावना भी जतायी गयी है कि भारत की जीडीपी 2030 तक सात प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भी भारत के वित्तीय क्षेत्र में आयी मजबूती और सरकार द्वारा किये गये हालिया संरचनात्मक सुधारों के कारण इस दावे की पुष्टि की है। एसएंडपी ग्लोबल ने अपनी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 की रिपोर्ट 'न्यू रिस्क, न्यू प्लेबुक' में कहा है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जायेगी। हाल के महीनों में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन एशिया में अपने समकक्ष बैंकों की तुलना में सबसे अच्छा रहा है।

देश के तीन बड़े बैंकों- भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक- ने 2023 में दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों की सूची में अपनी जगह बनायी है। एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय स्थिति में सुधार, मजबूत आर्थिक स्थिति, कर्ज में तेज वृद्धि, एनपीए में कमी और मुनाफे में इजाफे से भारतीय बैंक मजबूत हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में बैंकों की संपत्ति 50.5 प्रतिशत बढ़कर 1.51 लाख करोड़ डॉलर हो गयी है। हाल के महीनों में भारतीय बैंकों द्वारा दिये जा रहे कर्ज में तेज वृद्धि हुई है। उनतीस दिसंबर, 2023 तक यह 15.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गयी थी, जो एक वर्ष पहले 14.9 प्रतिशत थी।

बिजली कटौती और दाम बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन

प्रदेश के सभी 307 संगठन ब्लॉकों में दिया गया धरना

रायपुर। बिजली कटौती और बिजली के दामों की बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपा। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है बिजली की कटौती से जनता परेशान है। बिजली कटौती और महंगी बिजली के कारण परेशान जनता की आवाज को उठाने कांग्रेस ने जनआंदोलन छेड़ा है।

कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता गण अपने-अपने क्षेत्रों के ब्लॉकों में आयोजित धरनों में शामिल हुये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के धरने में शामिल हुये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजधानी के राजीव गांधी चौक के धरने में तथा पूर्व मुख्यमंत्री कुशालपुर रिंग रोड, सिद्धार्थ चौक, राजीव गांधी चौक के धरने में शामिल हुये। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जांजगीर-चांपा सक्ती के धरने में शामिल हुये।

राजधानी रायपुर के धरने को संबोधित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले 6 माह में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो-चार घंटे के लिये बंद न हो, रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयावह हो जाती है, घंटो बिजली गोल हो जाती है। भाजपा से न सरकार संभल पा रहा और न ही व्यवस्थायें। सरकार एक तो पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही, ऊपर से उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। प्रदेश के अनेक जिलों में तो पूरी रात बिजली कटौती हो रही है। भाजपा सरकार में आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली की खरीदी किया जाता था और आम जनता को 24 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती थी। रवि फसल लगाने वाले किसानों को भी बोरवेल चलाने के लिए बिजली निःशुल्क मिलता था। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना शुरू किया था जिसका लाभ प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था जिसे 5 साल में प्रत्येक उपभोक्ता का 40 से 50 हजार रु. तक की बचत हुई है। 1000 रू. महीना महिलाओं को देकर भाजपा सरकार बिजली बिल के रूप में दुगुना वसूल रही है। धरने को संबोधित करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय पूरे 5 साल सरप्लस बिजली छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को मिलता रहा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद तेलंगाना, गोवा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यो को पवार एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत छत्तीसगढ़ से बिजली सप्लाई की जाती थी।

बिजली कटौती पर झूठा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस बताएं बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 5 साल में क्या किया?

रायपुर। भाजपा से पूर्व विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता रंजन साहू ने कांग्रेस के प्रदर्शन को नौटंकी करार देते हुए उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस यह बताएं कि 5 वर्षों में प्रदेश में बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़े इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए यह सब कर रहे हैं। श्रीमती साहू ने कहा कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 4 बार से ज्यादा बिजली टैरिफ बढ़ाया गया,बिजली उत्पादन करने वाले 2 बड़े प्लांट बंद हो गए,उत्पादन क्षमता बढ़ने की जगह घट गई,बिजली कटने का विरोध करने वाले नागरिक पर राजद्रोह का केस डाल दिया गया.

अग्नि वीर के लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने पहुंचे वित्त मंत्री

फिजिकल टेस्ट के लिए सही ट्रेनिंग बहुत जरूरी, प्रशिक्षण कैंप का लाभ उठाएं अभ्यर्थी : चौधरी

रायपुर। अग्नि वीर भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित हुए जिले के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी उनके बीच पहुंचे। उन्होंने कहा लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके लिए सही ट्रेनिंग जरूरी होती है। जिला प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है इसका पूरा लाभ उठाएं और चयन परीक्षा में अपना शत-प्रतिशत दें। गौरतलब है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। रायगढ़ जिले के लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट के पूर्व उन्हें पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने जिला प्रशासन

के अधिकारियों के साथ सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए है।

जिला पंचायत के सभाकक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बच्चों को अग्नि वीर में चयन के लिए बधाई देते हुए कहा कि फिजिकल टेस्ट के मापदंडों के अनुरूप सही ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है यह आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है जिससे आप फिजिकल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है की जिला प्रशासन द्वारा अग्निवीर में चयनित अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। जिसमें आपके रहने खाने का निःशुल्क इंतजाम किया जाएगा। यह सुनहरा मौका है इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो। अग्नि वीर में चयन से न केवल आपको देश सेवा का अवसर मिलेगा बल्कि आर्थिक संबल के साथ सैन्य अनुशासन भी आप सीख सकेंगे जो आपके जीवन को मजबूत आधार देगा। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अभ्यर्थियों के लिए प्रोटीन रिच खुराक की व्यवस्था और ट्रेनिंग के लिए जूते व ट्रैकसूट इत्यादि का भी प्रबंध करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अग्निवीर थल सेना के लिखित परीक्षा में चयनित जिले के अभ्यर्थियों के फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस लाइन में व्यवस्था की जा रही है। यहां अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण के साथ उनके रहने व खाने का इंतजाम भी होगा। उन्होंने बताया कि फिजिकल टेस्ट से पहले दो चरणों में यह ट्रेनिंग पुरी की जाएगी। पहले चरण में मुख्य प्रशिक्षण का आयोजन होगा। जिसके बाद टेस्ट से पहले पुनरू रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में सेना द्वारा फिजिकल टेस्ट के मापदंडों के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जिससे अभ्यर्थी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसमें पुलिस विभाग के पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के साथ ही पूर्व सैनिकों तथा खेल प्रशिक्षकों का सहयोग भी लिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि उर्दना पुलिस ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। ट्रेंनिंग माड्यूल के अनुसार वहां अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने बताया कि बच्चों के मेडिकल जांच के संबंध में भी तैयारी की जा रही है।

महावृक्षारोपण अभियानः मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा

छत्तीसगढ़ में 03 करोड़ 85 लाख पौधों का होगा रोपण

रायपुर। एक पेड़ मां के नाम'' महावृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक पौधा रोपित कर राज्य को हरा-भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन बनाये रखना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2024 को ''एक पेड़ मां के नाम'' वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

''एक पेड़ मां के नाम'' महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 85 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। राज्य में ''एक पेड़ मां के नाम'' महावृक्षारोपण अभियान 11 जुलाई शाम 4 बजे जैव विविधता पार्क, अटल नगर, नवा रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य अतिथ्य में और अध्यक्ष वन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। महावृक्षारोपण अभियान में अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री अरूण साव, विजय शर्मा एवं सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अभनपुर, इंद्र कुमार साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव के रूप में उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री साय के द्वारा वृक्षारोपण स्थलों का नामकरण स्थानीय देवी-देवताओं के नाम से करने का आह्वान किया गया है। राज्य के सभी जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आग, जामुन, बेल, कटहल, सीताफल, अनार, शहतूत, बेर, तेन्दू, गंगाईमली जैसे फलदार पौधे तथा लघु वनोपज एवं औषधीय प्रजाति के पौधों जैसे- हर्रा, बहेड़ा, आंवला, नीम, पुत्रन्जीवा, काला सिरस, रीठा, चित्रक आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में छायादार प्रजातियां बरगद, पीपल, मौलश्री, कदम, पेल्ट्राफार्म, गुलमोहर, करंज, अशोक, अर्जुन के साथ अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है।

शराब घोटाले पर नए खुलासे पर बोली भाजपा

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को दोनो हाथों से लूटाःदेवलाल ठाकुर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर हो रहे नित-नए खुलासों के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार की काली करतूतें जिस तरह बेपर्दा हो रही हैं, उससे छत्तीसगढ़ तो शर्मसार है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज भी बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर कोर्ट में पेश में चुनिंदा नेताओं को शराब सिडिकेट द्वारा हर माह 10-10 करोड़ रुपए पहुँचाए जाने और रकम पाने वाले नेताओं द्वारा शराब सिंडिकेट को प्रोटेक्शन दिए जाने का उल्लेख होना यह बताता है कि कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार भ्रष्टाचार में किस तरह डूबी हुई थी! भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि शराब की काली कमाई को रफ्तार देने अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी ने अपने गुर्गों तथा आबकारी विभाग के अफसरों की मदद से अन अकाउंटेड शराब खपाने का

टारगेट एक साल के बाद ही दोगुना कर दिया था। इस बात का खुलासा भी ईओडब्लू द्वारा कोर्ट में पेश चार्जशीट से हुआ है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह एक और ताजा खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर किए जा रहे मिथ्या प्रलाप पर करारा तमाचा है। बघेल अब प्रदेश को बताएँ कि वे अपना मिथ्या प्रलाप कब बंद करेंगे और शराब घोटाले के सच का सामना करने का माद्दा कब दिखाएंगे? श्री ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा किया गया शराब घोटाला छत्तीसगढ़ की राजनीति में किया गया सबसे घृणित कार्य है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि कोई ऐसी सरकार नहीं होती है जो अपने राजस्व पर ही डाका डालने का काम करे है, लेकिन भूपेश सरकार ने यह भी कर दिखाया। वह राजस्व, जो सरकार को मिलना होता है, प्रदेश सरकार उसकी कस्टोडियन होती है.

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

राजस्व पखवाड़े में पटवारियों की हड़ताल सरकार की फजीहत

रायपुर। भाजपा सरकार की बड़ी हास्यापद स्थिति हो गयी है, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही, राजस्व अमला हड़ताल पर है जिसको लेकर प्रचार प्रसार कर रही, मंत्री प्रेस कांफ्रेस लेकर बड़ी- बड़ी बाते करते है वही सरकार की फजीहत का कारण बना हुआ है। सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है और दावा कर रही है कि इस पखवाड़े के दौरान जितने राजस्व प्रकरण है उन्हे निपटा लिये जायेंगे। प्रदेश के सारे पटवारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गये है। यह सरकार के कामकाज की स्थिति है। सरकार जिस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है, उसे पूरा करने के लिये कोई कार्ययोजना नही है। राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पटवारी हड़ताल पर चले गये। विष्णुदेव साय की सरकार भगवान भरोसे चल रही है। 6 महीने ही हुये सरकार को बने लेकिन इस सरकार के कामों से हर वर्ग में निराशा है, जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 6 माह में ही सरकार में काम करने की संस्कृति नष्ट हो चुकी है। सरकार अनुभवहीन और अदूरदर्शी लोगों के हाथों में होने का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है।

भाजपा के घोषणा पत्र में सरकार बनते ही पंचायत सचिव को नियमित करने का वादा था

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार के द्वारा पंचायत सचिवों के संविलियन के लिए बनाई गई कमेटी पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से सरकार बनते ही पंचायत सचिवों को नियमित करने का वादा किया था, यहां तो उलटी गंगा बह रही है नियमितकरण के आदेश के बजाये कमेटी बनाया जा रहा है। कमेटी बनाकर पंचायत सचिव को ठगा जा रहा हैं। भाजपा का यह असल चरित्र है चुनाव के दौरान वादा करना और सत्ता मिलते ही वादा खिलाफी करना। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पंचायत सचिवों के साथ अनियमित कर्मचारियों को भी 100 दिन में नियमितकरण का ख्वाब दिखाया गया था। अब अनियमित कर्मचारियों की छटनी हो रही है। अतिथि शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएड वाले मामलों में कोर्ट में ठीक से पक्ष नही रखा गया। जिसके कारण बीएड कर चयनित युवाओं के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो गए और सरकार सिर्फ आश्वासन देकर खाना पूर्ति कर रही है।

किसान नकली खाद, अमानक बीज, नैनो यूरिया से परेशान

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि साय सरकार के संरक्षण में किसानों के साथ छल किया जा रहा है। विगत दिनों बस्तर के पखांजूर में नकली खाद से भरा ट्रक पकड़ा गया, सूचना के मुताबिक नकली खाद राजस्थान से मंगाया गया था, किसानों का आरोप है कि भाजपा शासित प्रदेशों से नकली खाद छत्तीसगढ में खपाए जा रहे हैं। हाल ही में बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील के सरकारी सोसायटी में अमानक नैनो यूरिया का मामला सामने आया था। भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ नकली खाद, अमानक बीज, नकली दवा, घटिया कीटनाशक और एक्सपायरी नैनो यूरिया खपाने का अड्डा बन गया है। कमीशनखोरी के लालच में भाजपाई किसान विरोधी षड़यंत्र रच रहे हैं। विगत दिनों ग्राम मुरता सेवा सहकारी समिति, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा में किसानों को इफको कंपनी के द्वारा निर्मित एक्सपायरी नैनो लिक्विड खाद बेचने का मामला सामने आया था और अब बस्तर में राजस्थान से आयातित नकली खाद प्रकरण साय सरकार के किसान विरोधी षडयंत्र का उदाहरण है। आखिर वैधता खत्म हो चुके खाद का भंडारण प्राथमिक सहकारी समितियों के गोदामों में क्यों किया गया?

कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं कभी उन्हे स्लीपर सेल, कभी सत्ता भोगी बोला जा रहा है

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से अब पार्टी संगठन सम्हाले नहीं सम्हल रहा है और इसी बौखलाहट में अब वह भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाषा बोलकर अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता-भोगी और न जाने क्या-क्या कहकर अपनी हताशा जगजाहिर कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं लेकिन कांग्रेस में कदम-कदम पर अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमानित करने मानो होड़ लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा पहुँची है और कांग्रेस के नेता फिर भी जुबानी तौर पर बेलगाम होते जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बैज अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता-भोगी बताकर कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं और इस खुशफहमी में हैं कि संघर्ष के साथी उनके साथ हैं। कांग्रेस के जितने बड़े नेता, जो खुद भी हार गए हैं और जिनकी वजह से कांग्रेस हारी, अब वह रोज कार्यकर्ताओं को कोस रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं! पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके कारण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी, लोकसभा चुनाव में 10 सीटें हारी, जिनके खिलाफ कार्यकर्ता लगातार चिठ्ठियाँ लिख रहे हैं.

अग्रसेन महाविद्यालय में एंकरिंग पर 10 को होगी कार्यशाला

रायपुर. अग्रसेन महाविद्यालय (पुरानी बस्ती) में, एंकरिंग के विभिन्न आयामों पर विषय-आधारित जानकारी के साथ ही प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आगामी 10 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा. महाराजाधिराज अग्रसेन शिक्षण समिति के अध्यक्ष एवं महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉ वी.के. अग्रवाल ने बताया कि यहाँ वर्ष 2006 से पत्रकारिता विषय का अध्यापन किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय से पढ़कर निकले अनेक छात्र देश और प्रदेश की विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थाओं में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं. वहीँ महाराजाधिराज अग्रसेन शिक्षण समिति के सचिव एवं महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर तथा वाणिज्य संकाय के विभागाध्यक्ष डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि महाविद्यालय में पत्रकारिता के विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए स्वयं का एक अत्याधुनिक स्टूडियो उपलब्ध है. साथ ही महाविद्यालय द्वारा संचालित इंटरनेट रेडियो अग्रवाणी का प्रसारण भी नियमित रूप से किया जा रहा है. इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ युलेन्द्र कुमार राजपूत ने बताया कि मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की बढ़ती सम्भावना को देखते हुए यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है. इस कार्यशाला में पत्रकारिता संकाय की विभागाध्यक्ष डॉ आकांक्षा दुबे द्वारा एंकरिंग के साथ ही पब्लिक स्पीकिंग, वॉइस ओव्हर, स्टेज एंकरिंग, माइक हैंडलिंग, समाचार वाचन एवं प्रभावी संचार के विषय में उपयोगी जानकारी दी जाएगी.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर दिए कार्रवाई के निर्देश

शहर के डेंगू संक्रमित स्थानों को तलाशेगा स्वास्थ्य अमला

रायपुर। जिले में डेंगू के संक्रमण को रोकने स्वास्थ्य अमला मैदान में उतरेगा और डेंगू संक्रमित स्थानों की तलाश की जाएगी। साथ ही डेंगू से बचाव के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए है। साथ ही शासकीय अस्पतालों को साफ-सफाई रखने को कहा है, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर डॉ. सिंह ने जिले में नए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे करने के निर्देश

दिए है। जिले में 4 लाख 50 हजार राशनकार्ड धारियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

कलेक्टर ने सी.जी.एम.एस.सी. को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही एन.आर.सी. पर रायपुर में 20 बेड बढ़ाने की, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी की सुझाव को पूरा करने के लिए कोविड वार्ड जिला चिकित्सालय पण्डरी में प्रस्ताव पारित कराने को कहा। कलेक्टर डॉ. सिंह ने मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के समीक्षा में पाया कि गर्भवती का पंजीयन प्रथम तिमाही में अर्बन रायपुर एवं तिल्दा का कम है, इसे बढ़ाने का निर्देश दिए। संस्थागत प्रसव सुरक्षित प्रसव कराने के लिए एवं हाईरिस्क गर्भवती को समय पर एफ.आर.यू. रिफरल करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि प्रति गुरूवार को सुपरवाईजर को फिल्ड में जाकर रिपोर्ट कलेक्ट करें। कोई भी संस्था बंद न रहे। साथ ही मातृत्व मृत्यु की जानकारी लेने पर एम.सी.एच. नोडल द्वारा मातृत्व मृत्यु की कारणों की जानकारी बताई गई, जिसमें 3 केस की मृत्यु पी.पी.एच., हार्ट प्राब्लम, टी.बी. से मातृ मृत्यु होने की जानकारी दी गई। परिवार नियोजन में पखवाड़ा के अंतर्गत जिले में पुरूष नसबंदी अधिक से अधिक करने के निर्देश दिए है। साथ ही टीकाकरण रिपोर्ट में सुधार करने एवं कार्यक्रम अधिकारी एवं सलाहकार को अच्छे से मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। आर.बी.एस.के. टीम के कार्यों व प्रगति से कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उनकी विजिट आंगनबाड़ी एवं स्कूल में कम है एवं उनकी रिपोर्ट में विभिन्नता दिखी, जिस पर कलेक्टर ने नोडल अधिकारी एवं सलाहकार को फिल्ड स्तर में सुधार करने को कहा।

भारतीय बौध्द महासभा ने प्रतिभावान बच्चों का मोमेंटो प्रशस्ति पत्र से किया सम्मानित

रायपुर। भारतीय बौद्ध महासभा जिला इकाई रायपुर द्वारा आयोजित कैरियर एवं गाइडेंस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉ के.पी. यादव ने सफलता के लिए लगातार प्रयास एवं अनुशासन को जीवन में लाना अनिवार्य बताया। उपयुक्त विषय का चयन, सभी विषयों की महत्वता पर गाईड किया। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सही तैयारी कैसे किया जाए जानकारी दी। कार्यक्रम के आरंभ में भंते मेतान्द द्वारा बुद्ध वंदना कर माल्यार्पण किया गया। अतिथि गण बी, एस, जागृत प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, संजय गजघाटे ज्वाइन डायरेक्टर उद्योग

विभाग, भोजराज गौरखेड़े प्रदेश महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा, का स्वागत जिला समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला इकाई के अध्यक्ष प्रकाश रामटेके ने कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया। सेमिनार में पंजाब नेशनल बैंक CAC PNB से भोई एवं रेवती रंजन बेहरा, ने हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल लोन कैसे प्राप्त करें एवं इसकी आवश्यकता पर संपुर्ण जानकारी प्रदान की। मिलिंद माटे ने बैंक के द्वारा अन्य सुविधाओं का विस्तार से वर्णन किया, ज्वाइन डायरेक्टर संजय गजघाटे ने विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस के साथ सभी परीक्षाओं के इंटरव्यू फेस करने कहा। कार्यक्रम में इस वर्ष के 10 वी एवं 12 वी के मेधावी बच्चों को मोमेंटो एवं प्रस्तिपत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.